सम्पादकीय

वृद्धि और महंगाई में नाजुक संतुलन

पिछले तीन साल के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8 प्रतिशत सालाना से ऊपर की वृद्धि हासिल करने के बाद अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में केवल 5.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर पाई। पिछली सात तिमाहियों में यह वृद्धि का सबसे कम आंकड़ा रहा। इस तिमाही में आर्थिक सुस्ती का अंदाजा तो लगाया जा रहा था मगर इतनी सुस्ती का अनुमान तो बाजार भी नहीं लगा पाया था। लगभग उसी समय अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण मुद्रास्फीति की दर 6 प्रतिशत के सहज दायरे से ऊपर निकल गई। खाद्य मूल्यों में लगातार उछाल ने मुख्य मुद्रास्फीति पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए हैरत नहीं हुई, जब राजनीतिक हलकों से दर कटौती का इशारा आने के बाद भी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मुख्य मुद्रास्फीति लक्ष्य पर ही ध्यान दिया और दरें जस की तस रखीं। दूसरी तिमाही में मंद वृद्धि से प्रश्न उठता है कि यह एकबारगी फिसलन थी या लगातार तिमाहियों में वृद्धि दर घटते रहने से मान लिया जाए कि बुनियादी तौर पर मंदी आ रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में केवल 6 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है और अगली दो तिमाहियों में इसके रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। इसके बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक के वृद्धि का अपना अनुमान 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया। वृद्धि में सुस्ती और मुद्रास्फीति में उछाल के कारण एमपीसी को अब भी तलवार की धार पर चलना पड़ रहा है यानी नाजुक संतुलन बिठाने की कवायद अब भी जारी है। गिरती वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए दरों में कटौती शुरू करना जरूरी है और कुछ वर्गों से कहा भी जा रहा है कि रिजर्व बैंक को शीर्ष मुद्रास्फीति के बजाय मुख्य मुद्रास्फीति पर निशाना साधना चाहिए। मगर रिजर्व बैंक शीर्ष मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बांधने का संकल्प दोहरा चुका है और इसीलिए वह ढिलाई नहीं बरत सकता। इसलिए हैरत नहीं हुई, जब एमपीसी ने बहुमत वाला निर्णय लेते हुए नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया मगर नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) को दो किस्तों में 25-25 आधार अंक कम करने की बात कही। यह कमी 14 दिसंबर और 28 दिसंबर को की जाएगी, जिसका मकसद पर्याप्त तरलता बनाए रखना है। इस फैसले से साफ संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक के नीति संबंधी रुख में वृद्धि अहम है। सीआरआर कटौती से नकदी की स्थिति सुधरेगी, जो कर भुगतान के कारण तंग हो गई थी। साथ ही इससे बाकी दो तिमाहियों में सरकार के बढ़े पूंजीगत व्यय के लिए रकम भी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। विनिमॉण में निवेश वापस लाने के लिए यह बहुत जरूरी है। लेकिन दरों में कटौती का सिलसिला हाल फिलहाल शुरू होता नहीं दिखता। वर्तमान स्थिति में नीतिगत प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि इसे फौरी तौर की परेशानी माना जा रहा है या किसी बड़ी परेशानी की जड़ें जमने का संकेत समझा जा रहा है। रिजर्व बैंक के नीतिगत बयान में इस स्थिति को 'वृद्धि और मुद्रास्फीति के रास्ते से विचलन' बताया गया है। ऐसा मानने की वजहें भी हैं। मगर खनन तथा विनिर्माण क्षेत्रों में मूल्य वर्द्धमन में आई तेज गिरावट चिंता का विषय है। इसी गिरावट की वजह से इन दोनों प्राथमिक क्षेत्रों की वृद्धि कम रही है। कृषि क्षेत्र में मूल्य वर्द्धमन अच्छी बारिश के बाद भी 3.5 प्रतिशत बढ़ा।

वन नेशन वन इलेक्शन : रिपोर्ट आने के बाद मोदी का सपना मूर्त रूप लेने को तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में कहा कि एक साथ चुनाव कराने को लेकर देशभर में बहस चल रही है। यह चर्चा लोकतांत्रिक तरीके से की जानी चाहिए। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के अपने सपने को साकार करने के लिए हमें ऐसे अनेक नए विचार जोड़ने होंगे। गौरतलब है कि 1951 से 1967 के बीच लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। 1951-52 में आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे।

अशोक भाटिया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को दो बिल पेश करने को मंजूरी दे दी। इसमें एक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ करने के लिए और दूसरा दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के लिए समान संशोधन करने के लिए था। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को आखिरकार केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। सूत्रों के अनुसार विधेयकों को मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। ज्ञात हो कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार (14 मार्च) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। यह 18,626 पन्नों की है। इसमें कहा गया है- पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। यह रिपोर्ट स्टेकहोल्डर्स-एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है।रिपोर्ट के मुताबिक, 9%के देश, एक चुनाव% पर कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क साधा था। इनमें से 47 ने जवाब दिया। 32 पार्टियों ने एकसाथ चुनाव कराने का समर्थन किया, 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया और 15 पार्टियों ने इसका जवाब नहीं दिया। कांग्रेस, ब्ज बसपा और इब्बु-रू ने एक देश, एक चुनाव प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भाजपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने समर्थन किया।हाईकोर्ट के 9 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि ।ष्ट के 3 मुख्य न्यायाधीशों ने एक देश, एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध किया।

1959 में सीपीआई नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1960 में केरल में विशेष राज्य चुनाव हुआ था, जिसके चलते 1962 में राज्य सरकार भंग नहीं हुई थी, जब आम चुनाव हुए थे। 1964 में केरल में दोबारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फिर 1965 में चुनाव हुए थे लेकिन राष्ट्रपति शासन जारी रहा और 1967 तक चला, जिसके चलते केरल विधानसभा का चुनाव एक बार फिर आम चुनाव के साथ हुआ। 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने की वजह से पहली बार एक साथ चुनाव होने का चक्र बाधित हुआ था। वहीं, चौथी लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई थी, जिसकी वजह से 1971 में नए चुनाव हुए। बता दें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को सामान्य कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है।2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अब तक कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। अप्रैल-मई 2019 से शुरू होकर अब तक कई राज्यों के चुनाव हुए। वर्तमान में हर साल करीब 5-7 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं। बार-बार चुनाव होने की वजह से सार्वजनिक जीवन बाधित होता है। 2015 में कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा था कि बार-बार चुनाव होने से सामान्य सार्वजनिक जीवन में व्यवधान होता है और जरूरी सेवाओं के कामकाज पर असर पड़ता है। राजनीतिक रैलियां करने से सड़क यातायात बाधित होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है।मौजूदा चुनावी चक्र में शामिल प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्यों और शासन पर असर डालते हैं। बार-बार चुनाव होने के कारण सरकार और अन्य हितधारकों को बड़े पैमाने पर खर्च करना पड़ता है। काफी लंबे समय तक सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती है। आलोचकों की राय में एक साथ चुनाव कराने का विचार राजनीति से प्रेरित है। एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं का व्यवहार इस रूप में प्रभावित हो सकता है कि वे राज्य के चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करने लगेंगे। इससे संभावना है कि बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में जीत हासिल करें। इससे क्षेत्रीय पार्टियों के हाशिए पर चले जाने की आशंका है जो अक्सर स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं।कुछ आलोचकों का मानना है कि प्रत्येक 5 साल में एक से ज्यादा बार मतदाताओं का सामना करने से नेताओं की जवाबदेही बढ़ती है और वे सतर्क रहते हैं। कुछ राजनीतिक दलों और 2015 में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने एक बार में कराए जाने वाले चुनाव का समर्थन किया था। एआईएडीएमके ने गहन विचार-विमर्श के साथ वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया था। असम गण परिषद का कहना था कि इससे छोटी पार्टियों पर वित्तीय बोझ कम होगा। आईयूएमएल के मुताबिक ऐसा करने से समय की बचत होगी। डीएमडीके ने लोकसभा और विधानसभाओं के निश्चित कार्यकाल वाले विचार का समर्थन किया। वहीं, शिरोमणि अकाली दल ने इस विचार का समर्थन किया लेकिन कहा कि त्रिशंकु विधानसभा होने पर स्पष्टता की जरूरत है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध किया है। ममता बनर्जी ने आज दोपहर एक्स हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं द्वारा उठाई गई हर जायज चिंता को नजरअंदाज करते हुए असंवैधानिक और संघीय-विरोधी एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को अपना रास्ता बना लिया है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'एक देश, एक चुनाव' व्यवस्था लागू करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दिये जाने के बाद बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि सरकार चुनावी शुचिता पर उठ रहे सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी के रुख में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। खरगे ने समिति को इस साल 17 जनवरी को पत्र लिखकर 'एक देश, एक चुनाव' के विचार का पूरजोर विरोध किया था। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने बृहस्पतिवार को कहा कि पहले भी उनकी पार्टी ने चुनाव, चुनावी प्रणाली और चुनावी शुचिता से संबंधित कई सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 83(2) लोकसभा के लिए इसकी पहली बैठक की तारीख से पांच साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है, जब तक कि इसे पहले भंग न किया जाए। अनुच्छेद 172 (1) राज्य विधानसभा के लिए उसकी पहली बैठक की तारीख से पांच साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है।क्या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? इसका जवाब है कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी कीमत पर सदन का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता है लेकिन इसे इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग किया जा सकता है। एक साथ चुनाव पर चुनाव आयोग ने पहली बार 1983 में सुझाव दिया था। उस वर्ष प्रकाशित भारत के चुनाव आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट में इसका विचार आया था। विधि आयोग की ओर से 1999 में इसका विचार आया था। 1999 में न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने चुनावी कानूनों के सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट पेश की थी। इसने चुनाव सुधारों के एक भाग के रूप में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। 2015 में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में दीर्घकालिक (लंबे समय तक) सुशासन के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था और इसकी व्यवहार्यता की भी जांच की।2017 में नीति आयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। 30 अगस्त, 2018 को जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में भारत के विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित कानूनी और संवैधानिक सवालों की जांच की गई।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आज कई दिशा स्थानों की वृद्ध होगी। कुछ अच्छा तथा लाभकारी समाचार है कि आपके जीवन के ऐसे तीसरे क्षेत्र है, जहां आपके विरोधी कुछ होंगे और दुखी रहेंगे, आपकी मित्र बनी रहे तथा सहायक रहेगा। ज्ञात रहे किसी हमारे स्थान में और अंदाज हमारी को सुनकर्ता रहना सहायकारक अन्य को सलाह देनेवे, संबंध पारस्परिक संबंधों में वो, तथा यह सहायकारक सभी संबंध और बातों में सफल प्रदान करेगा

मेष
आज आप धार्मिक कामों में दिन गुजारने वाले हैं। हालांकि निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए आप अतिरिक्त मेहनत करेंगे। घर के अन्य सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है।

वृष
नौकरी या व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी आय बढ़ेगी। दांपत्य जीवन में वातावरण आनंदमय रहने का योग बन रहा है। आप में परोपकार की भावना रहने से अन्य लोगों की सहायता करने के लिए आप उत्सुक रहेंगे।

मिथुन
सभी काम व्यवस्थित रूप से पूरे होने की संभावना है। आज आपके कोई नए संबंध बनेंगे, जो आपके लिए भविष्य में आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगे। वैचारिक रूप से आप समृद्ध बने रहेंगे। शरीर, स्वास्थ्य और मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क
स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ थकान या आलस्य का अनुभव हो सकता है। संतान की पढ़ाई-लिखाई और स्वास्थ्य के विषय में भी चिंता रहेगी। व्यर्थ के खर्च से आज दूर रहें। आज आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। ज्यादा सोचने-विचारने से आप परेशान रहेंगे।

सिंह
व्यापार या नौकरी के कारण कहीं बाहर मीटिंग में जाना हो सकता है। अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। आज का दिन मध्यम फलदायी है। बौद्धिक तथा लेखनकार्य से जुड़े जातक आज ज्यादा सक्रिय रहेंगे। साहित्य में कोई नया सृजन कर पाएंगे।

कन्या
आप अपनी वाणी से किसी को मंत्रमुग्ध कर पाएंगे। आपकी वैचारिक समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आज मेहनत की अपेक्षा परिणाम कम मिलने पर भी निराश नहीं होंगे। धन की व्यवस्थित योजना बनाने के लिए आज का दिन अनुकूल है। अधिकारी आपसे खुश रहेंगे।

तुला
अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आय की अपेक्षा व्यय अधिक हो सकता है। ऐसे में संभलकर चलने की जरूरत है। आज का दिन आपके लिए लाभदायी रहेगा। मित्रों के साथ भेंट हो सकती है। घूमने-फिरने, आनंद-प्रमोद में दिन गुजरेगा।

वृश्चिक
काम में मिली सफलता आप के उत्साह में वृद्धि करेगी। विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। सम्बंधों में भावनात्मकता अधिक रहेगी। प्रवास भी आनंदमयी होने की पूरी संभावना है। समाज में खूब मान-सम्मान मिलेगा।

धनु
आज आपके मन में भांति-भांति के विचारों की तरंगे उठेंगी। आप कई तरह के विचारों में खोए रहेंगे। आज किसी के साथ भी वाद-विवाद ना करें। आज आप संवेदनशील रहेंगे। माता एवं पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है।

मकर
पारिवारिक जीवन में उल्लसमय वातावरण रहेगा। आज का दिन आपके लिए प्रतिकूल रह सकता है। मानसिक रूप से भी आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। आपकी वाणी से किसी का दिल दुख सकता है।

कुंभ
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी है। परिजनों के साथ आप अच्छी तरह से समय गुजार सकेंगे। दोस्तों का अच्छा साथ मिल सकता है। आर्थिक क्षेत्र में आय की अपेक्षा व्यय ही अधिक होगा। आज मीठी वाणी से सबका मन जीत लेंगे।

मीन
यात्रा के योग रहेंगे। किसी पानी वाली जगहों से आज दूरी बनाए रखें। मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है। आज का दिन खुशी से भरा रहेगा। नए काम की शुरुआत आज कर सकते हैं। मित्रों और रिश्तेजनों से मुलाकात हो सकती है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं। आईएफएस श्री बालाजी करी। जंगल के संरक्षण और संवर्धन के लिए इनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है। बेहद संवेदनशील व्यक्तित्व और सरल हृदय के धनी हैं करी। वर्क इज वर्कशिप के बेस पर काम करने की इनकी अद्भुत कला को बेहद करीब से देखने का मौका मिला। 06 जनवरी सन 1979 को गुंटूर में जन्में बालाजी करी एमएससी(कृषि -कीटविज्ञान) की शिक्षा के बाद सिविल सर्विसेज में आए और आईएफएस बने और जंगल के जीवों की सुरक्षा का वादा किया और निभाया। अलवर उपवन संरक्षक के दौरान हमने खुद इनकी शानदार कार्यशैली को देखा है। आज ये उप वन संरक्षक, आईसीएफआरई वन जैव विविधता संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना पद की सुशोभित कर रहे हैं। इससे पूर्व सहायक महानिरीक्षक वन, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा। उप वन संरक्षक, उदयपुर उत्तर। उप वन संरक्षक, वन्यजीव माउण्ट आबू। उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक, बाघ परियोजना सरिस्का। सहायक वन संरक्षक एवं प्रभारी उप वन संरक्षक, बीकानेर। उप वन संरक्षक पाली। उप वन संरक्षक, राजसमंद। सहायक वन संरक्षक एवं प्रभारी उप उपवन संरक्षक, करौली रहे हैं। बाघों के संरक्षण में महती भूमिका निभाने वाले शानदार वनाधिकारी के रूप में इन्हे जाना जाता है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

श्री बालाजी करी
(आईएफएस)

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

14 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- रुआल आमुन्सन 1911 में दक्षिणी ध्रुव की यात्रा।
- एनी बेसेन्ट को 1921 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने 'डॉक्टर ऑफ़ लेटर्स' की उपाधि से विभूषित किया।
- सन 1922 में यूनाइटेड किंगडम में आम चुनाव।
- ब्रिटिश उपनिवेश जिब्राल्टर एवं स्पेन के बीच स्थित विशाल ग्रीन गेट 1982 में 13 वर्षों के बाद पुनः खोला गया।
- जनरल हुसेन मोहम्मद इरशाद ने 1983 में खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया।
- बोरिनया, सर्बिया और क्रोएशिया के नेताओं ने 1995 में पेरिस में डेटन संधि पर हस्ताक्षर करके साढ़े तीन साल से जारी बाल्कन युद्ध को समाप्त किया था।
- ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के लिए 1997 में विश्व के सभी देश सहमत।
- सन 1998 में हुए 23वें काहिरा अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में तमिल फ़िल्म 'टेरिस्ट' में सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए आयशा धारकर को ज्यूरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया।
- जॉर्ज वॉकर बुश 2000 में अमेरिका के 43 में राष्ट्रपति निर्वाचित।
- पाकिस्तान ने 2002 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर नेत्रहीनों का विश्वकप जीता।
- मैक्सिको के मेरिदा में 2003 में पहले भ्रष्टाचार निरोधक समझौते पर 73 देशों ने हस्ताक्षर किये।
- वाली समझौते के प्रारूप से विवादित प्रावधान 2007 में अलग किये गए।
- भारत ने 2008 में अर्जेन्टीना के खिलाफ़ अंडर-21 हॉकी टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच 4-4 से ड्रा खेला।

जन्म 1864 में हुआ था।
- निबन्धकार, लेखक, कहानीकार उपेन्द्रनाथ अश्क का जन्म 1910 में हुआ था।
- प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु बी. के. एस. अयंगर का जन्म 1918 में हुआ था।
- नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी भौतिक विज्ञानी निकोले बासोव का जन्म 1922 में हुआ था।
- भारतीय अभिनेता राज कपूर का जन्म 1924 में हुआ था।
- प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का जन्म 1934 में हुआ था।
- भारतीय सिनेमा में बंगाली और हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत चटर्जी का जन्म 1936 में हुआ था।
- भारतीय नेता इंदिरा गाँधी के छोटे पुत्र संजय गाँधी का जन्म 1946 में हुआ था।
- भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज का जन्म 1953 में हुआ था।

14 दिसंबर को हुए निधन

- अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन (प्रथम) का निधन 1799 में हुआ।
- परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक और फ़्लाइंग ऑफ़िसर निर्मलजीत सिंह सेखों का निधन 1971 में हुआ।

14 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

- अपने समय में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध वकील और प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता जगत नारायण मुल्ला का

विशेष आलेख

एशिया, यूरोप और नाटो के शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका

संजीव ठाकुर

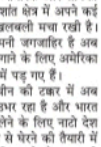

रूस में यूक्रेन पर आक्रमण कर के अमेरिका तथा यूरोपीय देशों के नाक में दम कर के रखा हैवह रूस का कहना है कि यदि यूक्रेन में नाटो देश अपनी सेना का लश्कर उतारेगा तो नाटो देश को भुगतना पड़ेगाइस श्रृंखला में इसराइल ने फिलीस्तीन लेबनान और ईरान पर अपना रोड रूप दिखाना शुरू कर दिया है इजराइल में हम आपका फिलिस्तीन को को लगभग नेस्तनाबूत कर दिया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस नेम इजरायल के राष्ट्र प्रमुख नेताओं के खिलाफ सामूहिक हत्याकांड का प्रकरण दर्ज किया है पर इजरायल को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो दुगनी ताकत से हमास फिलिस्तीन लेबनान और ईरान पर लगातार हमला कर रहा है लाखों नागरिक और सैनिकों की मौत भी हो गई है। चीन ने प्रशांत क्षेत्र में अपने कई युद्धपोत उतारकर नाटो देशों में खलबली मचा रखी है। अमेरिका की चीन से खाटी दुश्मनी जगजाहिर है अब चीन की ज्यादती ऊपर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका तथा नाटो देश बहुत गहरी चिंता में पड़ गए हैं।

यह भी तय है एशिया में चीन की टक्कर में अब भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत की सामरिक शक्ति का सहयोग लेने के लिए नाटो देश और अमेरिका भारत को हर तरह से घेरने की तैयारी में है। अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही अमेरिका और भारत के नए समीकरण बनने के कगार पर हैं भारत एशिया की चीन के बाद दूसरी महाशक्ति बन चुका है और अमेरिका तथा नाटो देश ने भारत के साथ एशिया में शक्ति संतुलन बनाने की पूरी योजना तैयार कर ली है और इसी कार्यक्रम में भारत को नाटो प्लस में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया गया है। उल्लेखनीय है कि नाटो में कुल 31 देश शामिल है और नाटो प्लस इसके एक एक्सटेंशन की तरह ही है आपको बता दें की नाटो प्लस में शामिल पांच देश वर्तमान में है जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान ,दक्षिण कोरिया शामिल है और यह देश अपने-अपने हितों के कारण नाटो प्लस तथा अमेरिका से जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि इसमें एक भी अटलांटिक देश शामिल नहीं हैया नाटो प्लस में सम्मिलित देशों को सामूहिक सुरक्षा के दायरे में रखा गया है सुरक्षा कवच के तहत यह सामूहिक अवधारणा है कि इन देशों पर यदि कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो यह माना जाएगा की वह इन सदस्य देशों पर हमला कर रहा है और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नाटो देशों की होगी पर नाटो प्लस के देशों को सुरक्षा कवच के दायरे से बाहर रखा गया है। इन देशों को सामरिक सूचनाएं और सामरिक सहयोग प्रदान नाटो देश करता रहेगा।दूसरी तरफ नाटो देश और अमेरिका हमेशा युद्ध के समय सदस्य देशों को यूक्रेन की तरह धोखा देने में माहिर होने के लिए जगजाहिर हो चुके हैं ऐसे में भारत को नाटो प्लस में शामिल होने के लिए कई बार विचार करना पड़ेगाइ वैसे नाटो प्लस में शामिल होने के लिए अभी कंवल अमेरिकी सांसदों का प्रस्ताव ही पारित हुआ है और अमेरिकी सरकार का पक्का प्रस्ताव भारत को नहीं मिला हैइ पिछले 5 वर्षों से भारत नई शक्ति के रूप में तेजी से शक्तिशाली हुआ है और अमेरिका तथा यूरोपीय देश भारत को एशिया की चीन के बाद दूसरी बड़ी शक्ति मान कर उसे अपनी तरफ शामिल करने के लिए काफी हद तक इच्छुक हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैइ प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा में भविष्य में नाटो प्लस पर भी चर्चा हो सकती हैइ भारत के संबंध अमेरिका से पिछले एक दशक से थोड़े मधुर हुए हैं पर अमेरिका का जैसा भारत के साथ इतिहास रहा है उस पर आंख मूंदकर विश्वास किया जाना बहुत मुश्किल ही समझा जाएगा। अमेरिका पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपने मित्र राष्ट्रों पर एन वक्त में धोखा देने में माहिर है जिसके ताजा उदाहरण अफगानिस्तान और यूक्रेन की तरह देखा जा सकता हैइ अफगानिस्तान अमेरिका के धोखे के कारण तालिबानी आतंकवादियों के हाथ में चला गया और यूक्रेन पूरी तबाही के कगार पर बैठा हैइ उल्लेखनीय है कि यूरोपीय देश भारत को इनके खिलाफ इसेमाल करने की योजना भी बना सकता हैइ भारत की विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र चलने की रही है ऐसे में यदि किसी गठबंधन के तहत वह अमेरिका या यूरोपीय देशों के साथ सामरिक समझौता करता है तो वह भारत की नीति के विरुद्ध होगाइ वैश्विक परिवेश में शीत युद्ध की स्थिति बन चुकी है और भारत को अपनी विदेश नीति की स्वायत्तता पर हटके रहकर निरपेक्ष ही रहना चाहिए क्योंकि नाटो प्लस के देश ऑस्ट्रेलिया ,इजरायल, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और जापान विभिन्न तरीकों से अमेरिका तथा नाटो देश से अपने हित के लिए जुड़े हुए हैंइ नाटो प्लस में शामिल होने से निश्चित तौर पर चीन भारत से नाराज हो सकता है इसके अलावा अमेरिका तथा यूरोपीय देशों की गहरी निकटता से भारत का परंपरागत मित्र रूस जिसने भारत के युद्ध काल में हमेशा मदद की है बुरा मान सकता है इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिग रहकर एक संतुलन बनाकर यूरोपीय देशों से सुरक्षित मित्रता एवं सुरक्षित दूरी रखकर चलना होगा क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलता आया है जबकि नाटो देश एक मजबूत सैन्य संगठन की तरह स्थापित है और ऐसे में किसी सैन्य संगठन में शामिल होना भारत की नीतियों के विरुद्ध होगा और भविष्य में नुकसान भी हो सकता हैइ स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की स्वतंत्र विदेश नीति ही विकास का मूल मंत्र रही है वर्तमान में भारत के संबंध अमेरिका, यूरोपीय देश, रूस, यूक्रेन तथा खाड़ी देशों से अच्छे बने हुए हैं अब किसी ग्रुप विशेष से संबंध रखने पर भारत की स्थिति डांवाडोल हो सकती हैइ नाटो प्लस में शामिल किए जाने का प्रस्ताव केवल चीन को एशिया में चुनौती देने के लिए ही दिया गया है और निश्चित तौर पर भारत इस तरह किसी भी सामरिक शोषण के लिए तैयार नहीं होगाइ भारत की वर्तमान आर्थिक और सामरिक स्थिति लगातार अनथक मेहनत और प्रयासों से प्राप्त हुई है और इस में गति लाने के लिए भारत को कूटनीतिक विचार मंथन करके अमेरिका तथा नाटो देशों से एक सुरक्षित दूरी तथा मित्रता रखनी होगी।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीरपुरा रोड़ खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-मनुजा पालन*। प्रधान संपादक-राय विनाश विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-पेशाना सिंह का नोहर,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 14 दिसम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

सच्चा पड़ोसी वह नहीं जो तुम्हारे साथ, उसी मकान में रहता है, बल्कि वह है जो तुम्हारे साथ उसी विचार स्तर पर रहता है

-स्वामी रामतीर्थ

बन गई बात

एक देश-एक चुनाव' को लागू करने संबंधी विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी, मसौदा कानून मौजूदा शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार विधेयकों पर व्यापक विचार-विमर्श करने को इच्छुक है। जिन्हें संसदीय समिति को भेजे जाने की संभावना है। सरकार विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्षों से परामर्श करने की इच्छुक है। इसमें विधानसभाओं को भंग करने और एकसाथ चुनाव शब्द को सम्मिलित करने के लिए अनुच्छेद 327 में संशोधन करने से संबंधित प्रावधान भी है। सिफारिश में कहा गया है, विधेयक को कम से कम 50 फीसद राज्यों से अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक अन्य विधेयक केंद्र शासित

प्रदेशों व पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर से संबंधित तीन कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करने वाला सामान्य विधेयक होगा। अपने देश में एक चुनाव की बात अनूठी नहीं है। क्योंकि आजादी के बाद के वर्षों में भारत में एक ही चुनाव होता था। यानी सभी राज्यों के विधानसभा व लोक सभा चुनाव साथ हुआ करते थे। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही विभिन्न मौकों पर देश भर में एक चुनाव कराने की बात करते रहे हैं। हालांकि भारत में एक चुनाव कराना सरकार के लिए आसान नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री चाहते हैं राज्यों व केंद्र में साथ में चुनाव हों ताकि संसाधनों व धन का अपव्यय रोका जा सके। अभी साल में कई दफा देश में कहीं-न-कहीं चुनाव हो रहे होते हैं; जिन पर राजनीति होती रहती है, चुनाव आयोग व सुरक्षा तंत्र व्यस्त रहता है। विपक्ष को बार-बार उंगली उठाने का मौका मिलता है। सरकार की दलील है कि एक देश-एक चुनाव से राजकोष में बचत होगी। आचार संहिताओं के चलते विकास परियोजनाओं में रुकावटें नहीं आएंगी। चुनाव के दौरान काले धन के उपयोग के आरोपों से निपटने में एजेंसियों को सुविधा होगी। हालांकि इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि देश भर में जितने संसाधनों की जरूरत होगी, उसके लिए सरकार को बजट बढ़ाना होगा। देश के तमाम क्षेत्रीय व छोटे दलों के लिए एक साथ चुनाव का भारी नुकसान हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, विधानसभा व लोक सभा चुनाव के मुद्दे काफी अलग होते हैं। एक ही चुनाव होने पर इनका पैटर्न बदल जाएगा। क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ी राजनीतिक पार्टियों से मुकाबला करना दूभर हो सकता है, परंतु जैसा कि 62 दलों में से 32 चुनाव के पक्ष में हैं। 15 ने विरोध किया है। इसलिए सरकार आम सहमति बनाने का भरसक प्रयास करे।

सद्भाव से निकलेगा हल

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी अदालतों को निर्देश दिया कि जब तक वह उपासना स्थल अधिनियम 91 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उसका निपटारा नहीं कर देता तब तक कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। सर्वेक्षण का आदेश भी पारित नहीं किया जा सकता। पिछले दो-चार वर्षों से विशेषकर निचली अदालतों में इस आशय की याचिकाओं की झड़ी लग गई है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हिन्दुओं के पवित्र मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदों का निर्माण किया था। इसलिए इन्हें हटा दिया जाना चाहिए। अदालत में इस तरह के अनेक मुकदमे लंबित हैं, जिनमें वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद,

मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद और हाल ही में संभल की मुगलकालीन मस्जिद सहित अनेक मामले शामिल हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन जब शिखर पर था तब सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल अधिनियम 91 पारित किया था। इसमें अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को छोड़कर देश के अन्य धार्मिक स्थलों के स्वरूप को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बनाए रखने का प्रावधान है। इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं ने इसे अनुचित बताते हुए कहा है कि यह धर्म के पालन करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन की विशेष पीठ उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधता परिधि और दायरे की जांच कर रही है। जब से देश में तीर्थ स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए निकली अदालतों द्वारा आदेश पारित किया जा रहे हैं तब से देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं। संभल में सर्वे के दौरान उपजी हिंसा में चार लोग मारे गए और करीब 20-25 लोग घायल हो गए। वास्तव में मंदिर मस्जिद विवाद में मुख्य मुद्दा यह है कि हिंदुओं का आहत इतिहास बोध जो मुसलमान को अक्रांता मानता है, अपने मंदिरों का ध्वंसकर्ता मानता है उसे कैसे राहत दी जाए। यह नहीं लगता कि इस तरह की समस्या का समाधान कानून के पास है। जब तक ऐसे मामलों में दोनों पक्षों के बीच कोई अत्यधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बनेगा तब तक इसका कोई स्थाई समाधान दिखाई नहीं देता।

कटाक्ष/ कबीरदास

इट इज बहुतै डिफरेंट!

ये लो कर लो बात। मोदी जी की पार्टी और उनकी सरकार ने बांग्लादेश के हिन्दुओं के दुःख-दर्द की जरा सी सुध क्या ले ली, इन सेकुलर बालों के पेट में दर्द शुरू हो गया। बांग्लादेश पड़ोसी सही, पर ये मामला तो अंतरराष्ट्रीय हुआ। पर पट्ठों ने उसमें भी हिन्दुस्तान को घुसा दिया; जबकि बात-बेबात हरेक चीज में भारत को घुसाने के लिए, बेचारे संघी बेकार में बदनाम हैं। कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुध ली, बड़ा अच्छा किया, पर अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुध कब लीजिएगा, हुजूर! बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों से मोहब्बत, अपने देश के अल्पसंख्यकों को दुत्कार, यह तो अन्याय है सरकार!

मोदी जी की पार्टी वाले गलत नहीं कहते हैं--ये सेकुलर वाले मुसलमानों से मोहब्बत करते हों या नहीं करते हों, पर हिन्दुओं से नफरत जरूर करते हैं। तभी तो उन मोदी जी के हरेक काम में नुक्स निकालते हैं, जो हिन्दुओं को बचाने में जुटे हुए हैं, हिन्दुस्तान तो हिन्दुस्तान, दूसरे देशों में भी। और मोदी पार्टी यह भी झूठ नहीं कहती है कि हिन्दू खतरे में हैं; सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं बांग्लादेश वगैरह में भी। सच पूछिए तो हिन्दुओं के खतरे में होने को, मोदी-योगी आदि के राज से जोड़ना भी सरासर ज्यादती है। वर्ना बांग्लादेश में तो मोदी जी-योगी जी का राज नहीं है, वहां हिन्दू खतरे में कैसे हैं? हिन्दुओं के खतरे में होने का कारण है, जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस है, तो अडानी खतरे में है। अडानी खतरे में है, तो मोदी जी खतरे में हैं। मोदी जी खतरे में हैं, तो हिन्दू खतरे में हैं। हिन्दू खतरे में हैं, हिन्दुस्तान तो हिन्दुस्तान, बांग्लादेश में भी।

और हां, कम से कम हिन्दुओं को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश में तो हिन्दू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, पर भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार-वत्याचार नहीं हो रहे हैं। माना कि यहां-वहां लिंचिंग हो रही है, मस्जिदों-मजारों को खोदा जा रहा है, घरों पर बुलडोजर वगैरह चल रहे हैं, खास कानून वगैरह बन रहे हैं, पर अत्याचार...कभी नहीं। हिन्दुओं के शब्दकोष में अत्याचार का तो शब्द ही नहीं है। हिन्दुस्तान में हिन्दू जो कर रहे हैं, डिफरेंट है। बांग्लादेश में हिन्दुओं के साथ जो हो रहा है, डिफरेंट है। वहां मुसलमान, वहां हिन्दू; इट इज बहुतै डिफरेंट!

सौहार्द ही अंतिम विकल्प

जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी, अब उसी के साथ भारत के रिश्ते अभूतपूर्व तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। वहां चार महीने पहले निर्वाचित सरकार के तख्तापलट और उसके बाद अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण ले लेने के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते तो तल्ख हुए ही हैं, साथ ही बांग्लादेश में रह रहे हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हिंसक हमलों की घटनाओं से भी दोनों देशों के रिश्तों में खासी कटुता आ गई है।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि बांग्लादेश में ऐसे लोगों की बढ़ी तादाद हो गई है जो अपने देश की पहचान 1971 के संदर्भ में नहीं, वहिब 1947 के संदर्भ में देखने लगे हैं। देश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस तो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी कह चुके हैं, 'बांग्लादेश बना, क्योंकि लोगों का उग्रवाद, बहुलवाद एवं धर्मनिरपेक्षता में गहरा यकीन था। अब दशकों बाद नई पीढ़ी उन मूल्यों और उसूलों पर पुनर्विचार कर रही है, जैसा कि 1952 में हुआ था, जब हमारे देशवासियों ने अपनी मातृ भाषा बांग्ला की रक्षा का संकल्प लिया था।' यानी 1952 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने मजहबी आधार पर बने राष्ट्र (पाकिस्तान) को नकार कर भाषा एवं संस्कृति पर आधारित बहु-धर्मीय राष्ट्र को स्वीकार किया था। लेकिन अब लगे 1947 की तरफ देख रहे हैं, जब भारत का मजहबी आधार पर विभाजन हुआ था।

अब बात चूंकि मुस्लिम पहचान पर आ गई है, तो स्वाभाविक नतीजा यह है कि वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के समान अधिकार की आकांक्षा पर चोट की जा रही है। इस रूप में पूरब की ओर भी पाकिस्तान की धारणा साकार हो रही है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त पर उभर कर सामने आया है, जब भारत उसे वैधानिक चुनौती देने के लिहाज से बेहद कमजोर स्थिति में है। चूंकि भारत में भी अब सत्ता प्रेरित मुख्य विमर्श हिन्दू-मुसलमान पर केंद्रित है, लिहाजा बांग्लादेश में हमेशा से मौजूद रही और अब सिर उठा कर सामने आ चुके महजबी कट्टरपंथी ताकतों को भी तर्क और ताकत मिल रही है। वैसे शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से वहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने भी पाकिस्तान से रिश्तों में गर्माहट लाने की दिशा में ऐसे कई ठोस कदम उठाए हैं, जो भारत के हित में नहीं माने जा सकते। पिछले महीने ही पाकिस्तान का एक मालवाहक पोत कराची से चल कर बांग्लादेश के दक्षिणपूर्वी तट स्थित चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के बाद से दोनों देशों में पहली बार

सीधा समुद्री संपर्क हुआ है। इससे पहले उनके बीच समुद्री व्यापार सिंगापुर या कोलंबो के जरिए होता था। खुद बांग्लादेश ने इस घटना को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत बताया है। कहा है कि इस रूट पर समुद्री संपर्क बनना दोनों देशों के बीच सप्लाई चेन को आसान बनाएगा, परिवहन के समय में कमी आएगी और आपसी व्यवसाय के लिए नये अवसरों के दरवाजे खुलेंगे।

जाहिर है कि यह सीधा समुद्री संपर्क पाकिस्तान और बांग्लादेश के राजनयिक रिश्तों में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। इसके पहले खबर आई थी कि दोनों देश एक परमाणु सहयोग समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके तहत पाकिस्तान परमाणु बिजली संयंत्र लगाने में बांग्लादेश की मदद करेगा। पूरा घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का पहलू है। आम संबंधों के साथ दोनों देशों के उग्रवादी तत्वों के बीच संपर्क बनना भी आसान हो सकता है। लेकिन इस मामले में भारत कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं दिखता।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर वहां की अंतरिम सरकार को अंतरराष्ट्रीय कठघरे में खड़ा करने की रणनीति पर राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की बजाय भारत में सियासी पार्टियां खासकर सत्तारूढ़ पार्टी राजनीतिक लाभ उठाने के अभियान में जुटी हुई हैं। भाजपा और उसके सहयोगी उग्र हिन्दूवादी संगठनों की ओर से देश में जगह-जगह बांग्लादेश के खिलाफ और वहां रह रहे हिन्दुओं के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करके उसे सबक सिखाने की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि पूरे बांग्लादेश को निकाने के लिए भारत के दो रफेल विमान ही काफी हैं।

बांग्लादेश का बिजली, पानी और दूध की आपूर्ति बंद कर देने की बातें कही जा रही हैं। मगर भारत में यह सब करने और कहने से बांग्लादेश के हिन्दुओं का भला होने की बजाय और नुकसान ही हो रहा है। यही वजह है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की के सदस्य गायेश्वर चंद्र रॉय को कहना पड़ा है कि उनके देश के मामलों में भारत दखलंदाजी करने और बांग्लादेश के राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने की कोशिशों से बाज आए। भारत में बांग्लादेश विरोधी उग्र प्रदर्शनों और बयानों के अलावा एक खतरनाक और विभाजनकारी सिलसिला और जारी है, जो आम में घी का काम कर रहा है। यह सिलसिला है-हर पुरानी मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढने का। आए दिन किसी न किसी प्राचीन मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। उपासना स्थल कानून, 1991 के मुताबिक 15 अगस्त, 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक समुदाय के उपासना स्थल को किसी दूसरे धार्मिक समुदाय के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता।

इस कानून की अनदेखी करते हुए निचली अदालतें भी बगैर सोचे-समझे ऐसी मस्जिदों और दरगाहों के पुरातात्विक सर्वे के आदेश धड़ल्ले से जारी कर रही हैं। हर मस्जिद और दरगाह के नीचे शिवलिंग खोजने और मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के अभियान से जो नफरत का माहौल आज भारत में बना हुआ है, वैसा ही हिन्दुओं के खिलाफ उन्मादी माहौल अब बांग्लादेश में भी है, जो कुछ महीनों पर पहले तक बिल्कुल भी नहीं था। कुल मिला कर यही कहा जा सकता है कि भारत में मुसलमानों को परेशान करने के लिए या बांग्लादेश में हिन्दुओं के उत्पीड़न के विरोध के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उससे बांग्लादेश के हिन्दुओं की दुश्वारियां कम होने की बजाय बढ़ ही रही हैं। *(लेख में विचार निजी हैं)*

बांग्लादेश में हिंसा

अनिल जैन

हर मस्जिद और दरगाह के नीचे शिवलिंग खोजने और मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के अभियान से जो नफरत आज भारत में है, वैसा ही हिन्दुओं के खिलाफ उन्मादी माहौल बांग्लादेश में भी है, जो कुछ महीनों पर पहले कतई नहीं था। यही कहा जा सकता है कि भारत में मुसलमानों को परेशान करने या बांग्लादेश में हिन्दू उत्पीड़न के विरोध के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उससे बांग्लादेश के हिन्दुओं की दुश्वारियां कम होने की बजाय बढ़ ही रही हैं

- दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशी का ध्यान रखना भूल जाने की मनोस्थिति को मनोवैज्ञानिक 'सोशियोट्रॉपी' कहते हैं। ऐसे लोगों को 'पीपल प्लीजर' कहते हैं। ये दूसरों की जरूरत का अपनी जरूरतों से ज्यादा ध्यान रखते हैं
- हालांकि समय तेजी से बदला है। लोग 'पीपल प्लीजर' की बजाय 'सेल्फ प्लीजर' पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। खासकर आज का युवा 'सेल्फ प्लीजर' की अहमियत समझता है
- युवा अपनी जिम्मेदारियां निभाते समय हताश व्यस्त नहीं होता कि अपनी खुशियों को ही दरकिनार कर दे। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी जिंदगी तमाम नहीं करता

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

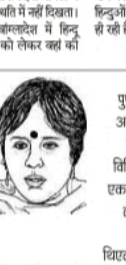

पुष्पा भगदड़ मामले में अलु अर्जुन की गिरफ्तारी और 14 दिन की हिरासत कहना होगा कि विचित्र बात है। घटना में 35 वर्षीया एक महिला की मौत वाकई दुखद है, लेकिन इसके लिए अलु अर्जुन पर आरोप लगा कर घटना के समय थिएटर में सुरक्षा और लॉजिस्टिक के लिए जिम्मेदार लोगों की चूक से ध्यान भटका दिया गया है।

बरखा दत्त, पत्रकार
@BDUTT

शतरंज | मनोज चतुर्वेदी

आनंद के कद पर पहुंचे गुकेश

दुनिया को सबसे कम उम्र वाला विश्व शतरंज चैंपियन मिल गया है। यह उपलब्धि पाने वाले हैं भारत के 18 वर्षीय ग्रैंडमास्टर डोम्मराजू गुकेश। यह भी संयोग ही है कि इस 18 वर्षीय खिलाड़ी ने 18वां विश्व खिताब जीता है। वह चीन के डिंग लिरेन को 7.5-6.5 अंकों से हराकर चैंपियन बने हैं। विश्व चैंपियनशिप की ट्रॉफी करीब 11 साल बाद भारत आई है। भारत के पहले विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को 2013 में कार्लसन से हारने पर ट्रॉफी देश से चली गई थी। गुकेश ने 2013 में सात साल की उम्र में जब शतरंज खेलना शुरू किया, तब वे उन्होंने इस विश्व खिताब को जीतने का सपना देखा था, जिसे वह एक दशक से कुछ ज्यादा समय में साकार करने में सफल हो गए हैं। गुकेश से पहले सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बनने का गौरव गैरी कास्परोव को हासिल था, उन्होंने यह उपलब्धि 22 साल की उम्र में हासिल की थी। वहीं आनंद पहली बार 31 साल की उम्र में चैंपियन बने थे।

सही मायनों में गुकेश के कॅरियर को नई ऊंचाइयां दिलाने वाला पिछला एक साल रहा है। इससे पहले शायद किसी ने भी उनके इतनी जल्दी चैंपियन बनने की कल्पना नहीं की थी। वह एक साल पहले फीडे रैंकिंग में 25 वें नंबर पर थे। यही नहीं वह भारत के भी पहले चार खिलाड़ियों तक में शामिल नहीं थे। उस समय उनसे आगे रैंकिंग में आनंद, प्रगनानंदा, अर्जुन एरिगेसी और विदित गुजराती थे। उनके कैंडीडेट टूर्नामेंट में खेलने की पात्रता हासिल करने पर भी उन्हें विश्व चैंपियन बनने का मजबूत दावेदार नहीं माना जा रहा था। पर इस युवा ने सभी को चकित करके कैंडीडेट टूर्नामेंट जीता और अब विश्व चैंपियन भी बन गए हैं। इन दो सफलताओं के साथ भारत के शतरंज ओलंपियाड का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम में भी वह शामिल थे। यह सफलताएं उनके लिए साल का यादगार बनाती हैं। चौदह बाजियों के इस मुकाबले की आखिरी बाजी में सफेद मोहरों से खेल रहे डिंग लिरेन और गुकेश द्वा की तरफ बढ़ते नजर आ रहे थे, यह लिरेन के लिए बेहतर संकेत था। इसकी वजह 14 बाजियों में अंक बराबर रहने पर टाइब्रेकर को अपनाया जाता, जिसमें रैपिड बाजियां खेली जातीं और इसमें लिरेन को बेहतर माना जाता है, लेकिन तब ही लिरेन 55वीं चाल में हाथी की गलत चाल चल बैठे और इस गलती को गुकेश ने जीत में बदलकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। लिरेन ने बाद में कहा कि मुझे अपनी गलती का अहसास चाल चलने के बाद हुआ। पर साथ ही यह भी कहा कि 13वीं बाजी में भाग्यशाली था, जो हार से बच गया था। मुझे हार का पछतावा नहीं है। मौजूदा समय में शतरंज सिर्फ

दिमाग का ही खेल नहीं रहा। इसके लिए खिलाड़ी को फिटनेस के साथ मेंटल स्ट्रेंथ पर भी काम करना पड़ता है। गुकेश ने मानसिक मजबूती के लिए मेंटल हेल्थ कोच पैडी अप्टन की सेवाएं लीं। पैडी भारतीय कोच के रहते भारत ने 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई में आईसीसी विश्व कप जीता था और व 2024 के पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के साथ भी वह जुड़े हुए थे। गुकेश के बारे में कहा जाता है कि वह झटका लगने पर जोरदारी से वापसी करना जानते हैं। अपनी यह खूबी उन्होंने इस मुकाबले में दिखाई भी। वह पहली ही बाजी हारने के बाद तीसरी बाजी जीतकर यह दिखाने में कामयाब रहे कि उनमें वापसी करने का माद्दा है। उन्होंने तीसरी बाजी के बाद 11वीं बाजी जीतकर अपनी बेहतर संभावनाएं बनाईं। पर 12वीं बाजी हारने से लगा कि खिताब हाथ से निकलने जा रहा है। पर वह लिरेन की गलती को अपने को चैंपियन बनाने में बदलने में सफल रहे। गुकेश भले ही जन्मजात प्रतिभा के धनी हैं पर उनके कॅरियर को एक साल पहले वेस्टब्रिज आनंद शतरंज अकादमी के साथ जुड़ने पर नया आयाम मिला है। आनंद गुकेश के चैंपियन बनने पर कहा कि यह भारत के लिए बहुत गर्व का क्षण है। यह शतरंज के लिए बहुत बड़ा गर्व का क्षण है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी गर्व का क्षण है। गुकेश ने इस सफलता को पाने के बाद कहा कि मुझे चैंपियन बनाने में विश्वनाथ आनंद की एक सलाह बहुत काम आई। उन्होंने बताया कि पहले ही दिन बाजी हारना बहुत परेशान करने वाला था। मैं जब लिफ्ट से अपने कमरे में जा रहा था, तब आनंद सर भी मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि 2010 की विश्व चैंपियनशिप में टोपालोव के खिलाफ पहली बाजी हारा था, तब मेरे पास 11 ही गेम थे, तुम्हारे पास तो अभी 13 गेम हैं। उनकी इस बात ने मेरे अंदर नया उत्साह भर दिया।

आनंद की विश्व शतरंज पर बादशाहत से भारतीय शतरंज को भरोसा मिला और अब यह गुकेश की सफलता दुनिया पर भारत का दबदबा बना सकती है। हमें याद है कि 1980 के दशक में आनंद जब ग्रैंडमास्टर बने थे, तब यह बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी, लेकिन आनंद के विश्व चैंपियन बनने ने भारतीय शतरंज की बिसात ही बदल दी और आज देश के पास 85 के करीब ग्रैंडमास्टर हैं। भारत की इस प्रगति में तमिनाडु प्रांत का बहुत बड़ा योगदान है। अकेले इस राज्य से 31 ग्रैंडमास्टर निकले हैं। इसमें भी करीब दो दर्जन ग्रैंडमास्टर चेन्नई से ताल्लुक रखते हैं। भारत के पास गुकेश जैसी क्षमता वाले प्रगनानंद, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती जैसे युवा है। अगर तमिलनाडु की तरह ही इसे देश के अन्य भागों में भी बढ़ावा दिया जाए तो भारत का शतरंज में ऐसा दबदबा बना सकता है, जैसा कभी सोवियत संघ का हुआ करता था।

समझदारी से निवेश | संत राजिन्दर

युगों युगों से सभी धर्मास्त्र हमें बताते चले आए हैं कि हम इस दुनिया में स्वांसों की सीमित संख्या के साथ पैदा होते हैं। हम अपनी सांसों की संख्या को एक बैंक के खाते या पूंजी की तरह समझ सकते हैं, जो हमें पिता-परमेश्वर द्वारा दी गई है। हम निर्णय करें कि हमें अपनी इन सांसों की पूंजी को कैसे खर्च करना है? अपनी इस पूंजी को हम समझदारी से या मूर्खता दोनों में से किसी एक तरह खर्च कर सकते हैं। जब हम समझदारी से अपनी सांसों की पूंजी जो हमें इस दुनिया में इस्तेमाल के लिए दी गई है उसे पिता-परमेश्वर की ओर निवेश करते हैं तो हम एक सच्चा निवेश कर रहे हैं, जिसका हमें भविष्य में अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। यह निवेश एक ऐसी मिठास का अहसास लाता है जो इस दुनिया में किसी भी वस्तुओं में नहीं मिल सकता है और यह वह मिठास है जो हमेशा बनी रहती है। सभी धर्मशास्त्र हमें यह समझाते हैं कि प्रभु में अपना समय निवेश करने का मतलब है कि हम अपना ध्यान सही दिशा में केंद्रित कर रहे हैं और अपने समय का उपयोग इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दे रहे हैं, जिसके लिए हम सब यहां इस दुनिया में आए हैं। जीकि जो अपने आपको जानना और पिता-परमेश्वर को पाना है। जिसे हम केवल ध्यान-अभ्यास द्वारा ही पा सकते हैं। जैसे ही हम अंतर में ध्यान टिकाते हैं और उस दिव्य-शक्ति से जुड़ते हैं जिससे सारी सृष्टि की रचना की है। तब हमारी आत्मा परमात्मा को पहचानती है और हम प्रभु के प्रेम, खुशी और आनंद को पा लेती है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यदि हम आत्मा का वैभव और चमक देखना चाहते हैं तो रोज़ाना कुछ समय के लिए ध्यान-अभ्यास में बिताने से हमें अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। प्रत्येक दिन कुछ समय ध्यान-अभ्यास में बैठने से पाएंगे कि हम अपने समय का उपयोग हमेशा आध्यात्मिक लाभ के लिए कर रहे हैं। आध्यात्मिक जागृति के साथ प्रभु के लिए हमारा प्रेम गहरा हो जाता है, जिससे हम भीतर से परिवर्तित होते हैं। प्रभु प्रेम से ओत-प्रोत हो जाते हैं, आत्मा पर चढ़े मन-माया और जड़ता के पर्दे हटते हैं। सत्गुरु के मार्गदर्शन से हमारे जीवन और मृत्यु के रहस्य खुलते हैं और आत्मा परमात्मा के पास जाने का रास्ता प्राप्त करती है।

रीडर्स मेल

नजर रखे सरकार

संयुक्त परिवार का विघटन, पश्चिमी जीवनशैली की नकल, रुचिकर स्वाद, आसानी से उपलब्धता, दिखावा का शौक एवं पति-पत्नी दोनों के कामकाजी होने की वजह से भी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का बाजार बढ़ता जा रहा है। डिब्बाबंद भोजन शरीर में मोटापा बढ़ाने के साथ कई अन्य जानलेवा बीमारियों की जनक है, जो प्रारंभिक दौर में पहचान में नहीं आती है, लेकिन कुछ समय के बाद यही बीमारियां हमारे जीवन के लिए नासूर बन जाती है। सरकार को कानून बनाकर सभी पैकिट्स पर खाद्य सामग्रियों पर वसा, नमक और चीनी एवं अन्य सामग्रियों की मात्रा का विवरण पैकेट पर उपलब्ध कराना चाहिए। डिब्बा बंद खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए।

हिमांशु शेखर, गया

न हो कानून का दुरुपयोग

बेंगलुरु में एक युवा प्रफेशनल द्वारा आत्महत्या करने का मामला बेहद दुःखद घटना है। आजकल के भागदौड़ व तनावपूर्ण माहौल में ऐसी घटनाओं का होना आम बात हो गई है। इस घटना के बाद एक बार फिर से इस बात पर बहस छिड़ गई है कि हमारे समाज व कानून में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा व अधिकार प्राप्त है। बेंगलुरु की घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही साथ ही इससे कई नए तरह के सवाल भी खड़े होते हैं कि विवाह के उपरांत पुरुष और उनके परिवार पर दहेज अथवा घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करके उनसे गुजारा भत्ता की राशि तो वसूल की ही जाती है साथ ही उनका मानसिक शोषण भी किया जाता है। ऐसे मामलों में बात उस समय और भी बेहद कष्टदायक बन जाती है जब कानूनों का दुरुपयोग करके किसी महिला द्वारा झूठा केस दर्ज कराकर किसी पुरुष को कानूनी मामलों में उलझाकर उसका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जाता है। हालांकि हर मामले में ऐसा नहीं होता। इस तरह के मामलों में अब कानून को बदलने की मांग भी उठने लगी है। बेंगलुरु में एक युवा प्रफेशनल ने जिन हालातों में आत्महत्या की है वो हमारे सिस्टम को भी कठघरे में खड़ा करता है। हमें कानून के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकना चाहिए।

हितेंद्र डेढ़ा, दिल्ली

संकट में राहुल गांधी

इन दिनों लोक सभा में विपक्ष के नेता का पद राहुल गांधी के पास है। वहीं इंडिया गठबंधन के मुख्य नेता भी है। मगर कहां जा रहा है कि इन दिनों अब उनका नेता पद डगमगा रहा है। एक समय था जब राहुल एवं अखिलेश यादव के बीच में गहरी दोस्ती थी, मगर अब लगता है दोनों के बीच दरार आ गई है। इसकी वजह कांग्रेस पार्टी द्वारा होने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर डाका डालना। अखिलेश यादव को अब यह बात समझ में आने लगी है कि कांग्रेस की हैसियत अब पहले जैसी नहीं रही है। इसलिए वह कांग्रेस से दूरी बनाने लगे हैं। इन दिनों जब से ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद स्वीकार करने की बात कही है तब से अखिलेश यादव ने भी उनके समर्थन का मन बना लिया है। कहा जा सकता है कि आज के समय में लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद एवं इंडिया गठबंधन के नेता का पद राहुल गांधी से अब छिन सकता है।

एमएम राजावतराज, शाजापुर, मप्र
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़ी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, स्वर्ण शतक, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश विश्वा* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23362368, 23362369, 23362371, 23362370, फैक्स - 23362370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 118
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस लेख में प्रकाशित समस्त सामग्री के कथन एवं संमति तथा कानूनी सामले के लिए उत्तरदायी

12 महिलाएं झारखंड विधानसभा पहुंची हैं इस बार चुनाव जीतकर। इसबार यह संख्या सर्वाधिक है। इससे पहले वर्ष 2000 में तीन, 2005 में आठ, 2014 में नौ और 2019 में 10 महिलाएं विधानसभा पहुंची थीं।

ड. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, वेन्टेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा

आजकल

दिमाग को जकड़ता इंटरनेट मीडिया

इंटरनेट मीडिया ने सभ्यता के इतिहास में शायद पहली बार हमारी मानसिक या बौद्धिक स्थिति को इतने गर्त में पहुंचा दिया है, जहां छिछले ज्ञान और बेहूदा मनोरंजन को भी लोग सहजता से ग्रहण करने लगे हैं। इससे पैदा हो रही मानसिक अवस्था को आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 'ब्रेन रोट' यानी दिमागी सड़न अथवा मानसिक जड़ता रूपी शब्द के रूप में दर्ज किया है। असल में इसने इंटरनेट मीडिया की उस बीमारी को उजागर करने का किया है, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक बेहद गंभीर समस्या बन गई है

वास्तविक जीवन पर हावी होती वर्चुअल जिंदगी। प्रतीकात्मक

सूचनाओं को अक्सर ज्ञानवर्धन के जरिये के रूप में रेखांकित किया जाता है। कहा जाता है कि वे सूचनाएं ही हैं, जो नई-नई जानकारियों के रूप में हमारे अज्ञान का नाश करती हैं और जीवन को एक अर्थ प्रदान करती हैं, पर जब सूचनाओं की बमबारी हो रही हो, हमारा मस्तिष्क किसी एक स्थान पर केंद्रित न रहकर जानकारियों के जंजाल में फंसकर तय नहीं कर पा रहा हो कि किस सूचना को ग्रहण किया जाए और किसे छोड़ा जाए, तब क्या होगा? ये सूचनाएं अर्थहीन तस्वीरों और वीडियो के रूप में हर क्षण हमारे मस्तिष्क के अधिकांश हिस्से को घेर ले रही हों, तब क्या स्थिति बनेगी? आश्चर्य नहीं कि इंटरनेट के रास्ते हर हाथ में समाए स्मार्ट फोन पर जिस इंटरनेट मीडिया ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, उससे पैदा हो रही मानसिक अवस्था को आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने "ब्रेन रोट" यानी दिमागी सड़न रूपी शब्द के रूप में दर्ज किया है। वर्ष 2024 के वर्ड आफ द यीअर के रूप में "ब्रेन रोट" का चुनाव करते हुए आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने असल में इंटरनेट मीडिया की उस बीमारी को उजागर कर दिया है, जो शायद पूरी दुनिया के लिए एक बेहद गंभीर समस्या बन गई है।

यह दिमागी जड़ता आई कहां से है? मानव सभ्यता का इतिहास देखें तो सबा दो सौ साल पहले शुरू हुए उद्योगीकरण तक इंसानों के पास ज्यादा सूचनाएं नहीं थीं, लेकिन उसका मानसिक विकास रुका नहीं। तमाम कलाएं विकसित हुईं, देरों साहित्य रचा गया, अनेक ब्रेमिस्लव आविष्कार हुए और सभ्यता विकास के उस शीर्ष पर पहुंची, जहां पर पहुंचकर इंसान इस ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रजाति बन गया, लेकिन

दैनिक जागरण
सपनों की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्न भी करने पड़ते हैं

संविधान पर चर्चा

यह अच्छा हुआ कि लगातार बाधित हो रही संसद में संविधान पर चर्चा के बहाने हंगामा थम गया और लोकसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष बहस करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन संविधान पर चर्चा के दौरान कुल मिलाकर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला ही आगे बढ़ता दिख रहा है। संविधान पर चर्चा के नाम पर उन्हीं मुद्दों को रेखांकित किया जा रहा है, जो पहले भी उठाए जाते रहे हैं और जिनके जरिये एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा किया जाता रहा है। संविधान पर लोकसभा में चर्चा के बाद राज्यसभा में भी उस पर बहस होगी। यह बहस पूरी होने पर ही यह पता चलेगा कि उसका निष्कर्ष क्या रहा, लेकिन जैसी शुरुआत हुई है, उसे देखते हुए यह नहीं लगता कि इस चर्चा से देश की जनता को कुछ हासिल हो सकेगा। संविधान पर चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि उसे अपनाए हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। संविधान पर विमर्श के लिए यह अवसर बिल्कुल उपयुक्त है, लेकिन सार्थक चर्चा का अभाव इस अवसर को गंवाने का ही काम करेगा। सत्तापक्ष के अनुसार वह संविधान के प्रति समर्पित है और मोदी सरकार उसी के अनुरूप आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष को ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। उसके अनुसार सरकार संविधान की भावना के प्रतिकूल कार्य करते हुए उसकी अनदेखी कर रही है।

विपक्ष के रवैये से यही साबित हो रहा है कि वह यह समझना चाहता है कि सरकार संविधान को बदलने का इरादा रखती है। यह वही पुराना आरोप है, जिसे लोकसभा चुनाव के समय जोर-जोर से प्रचारित किया गया था। इस प्रचार के चलते विपक्ष को कुछ राजनीतिक लाभ भी मिला था। लगता है कि विपक्ष ने यह मान लिया है कि उसकी ओर से संविधान खतरे में है का जो हौव्वा खड़ा किया जा रहा है, उससे उसे आगे भी राजनीतिक और चुनावी लाभ मिलेगा, लेकिन वह ध्यान रखे तो बेहतर कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। यह विचित्र है कि संविधान एक है, लेकिन उसके पालन के मामले में दोनों पक्षों का दृष्टिकोण एक-दूसरे के सर्वथा विपरीत है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? संविधान पर बहस का कोई लाभ तो तब मिल सकता है, जब वह इस पर केंद्रित हो कि उस पर सही तरह अमल कैसे हो और उन कारणों का निवारण कैसे किया जाए, जिनके चलते नियम-कानूनों का अनुपालन संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। यदि सत्तापक्ष और विपक्ष में संवैधानिक प्रविधानों के पालन को लेकर कोई सहमति ही नहीं बनेगी तो फिर संविधान पर चर्चा का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं कि संविधान को लेकर यह माहौल बनाया जा रहा है कि देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन करना उसे खत्म करने की कोशिश है। संविधान के प्रति धर्मग्रंथ जैसी आस्था रखना तो ठीक है, लेकिन उसे किसी धार्मिक ग्रंथ के समान बताने का कोई मतलब नहीं।

शिक्षा के लिए

प्रतियोगिता के इस दौर में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश सरकार इस संबंध में गंभीरता से कार्य कर रही है। शिक्षण संस्थानों में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों और शिक्षकों की कमी न हो, इसके लिए स्कूलों का युक्तीकरण किया जा रहा है। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी, उसे भी दूर किया जा रहा है। सरकार ने स्कूल प्रमुखों का यह शक्तियां भी दी हैं कि यदि कोई शिक्षक लंबी छुट्टी पर जाता है या किसी कारण स्कूल-कालेज में कुछ समय के लिए शिक्षक का पद रिक्त होता है तो वे अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें तय मेहनताना भी दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कई स्थानों पर सफलता भी मिली है, लेकिन सभी जगह स्थिति सुखद नहीं है। इस साल सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन सिस्टम फार स्कूल्स (यू-डाइस प्लस) की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पिछले वर्ष की अपेक्षा 53,109 कम बच्चों ने प्रवेश लिया। यह जानना आवश्यक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके प्रमुख कारण अभिभावकों का निजी स्कूलों की तरफ रुझान, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं शिशु जन्म दर में कमी बताए जा रहे हैं। सरकार के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षकों को भी बच्चों की संख्या में वृद्धि के लिए अधिक गंभीरता से प्रयास करने होंगे। अभिभावकों को विश्वास दिलाना होगा कि सरकारी स्कूल में उनके बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रयास फलीभूत होंगे, बच्चों की संख्या बढ़ेगी और उन्हें बेहतर शिक्षा मिलेगी।

> सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के प्रयासों में और गंभीरता की आवश्यकता है

बांग्लादेश को बदलना होगा रवैया

हर्ष वी. पंत

चूंकि बांग्लादेशी राजनीति की रंगत बदल गई है, इसलिए भारत को नई वास्तविकताओं के अनुरूप नए सिरे से कदम बढ़ाने होंगे।

अवधेश राजपूत

राजनीति बहुत ही संवेदनशील विषय है तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा उससे भी कहीं ज्यादा नाजुक है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की दशा-दिशा इसका जीवंत उदाहरण है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का परिदृश्य एकाएक कैसे पूरी तरह बदल जाता है। बदली हुई परिस्थितियों में द्विपक्षीय संबंधों पर मंडराते संशय के बादलों के बीच बीते दिनों विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बांग्लादेश का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 'सकारात्मक, रचनात्मक एवं परस्पर लाभ वाले संबंधों' की वकालत की। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी मिसरी के विचारों से सहमति जताई। हालांकि ऐसी औपचारिक बातों का तब तक कोई मतलब नहीं निकलता, जब तक कि वे धरातल पर आकार न ले सकें।

इसमें कोई संदेह नहीं कि शेख हसीना के तख्तापलट के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में गतिरोध की आशंका जताई जा रही थी और वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। शेख हसीना के कार्यकाल में दोनों देशों ने सुरक्षा से लेकर आर्थिक मोर्चे पर सहयोग के नए प्रतिमान स्थापित किए और लोगों का आपसी संपर्क-समन्वय भी बेहतर हुआ। याद रहे कि 2009 में शेख हसीना के सत्तारूढ़ होने से पहले द्विपक्षीय संबंध बहुत खराब हो चले थे। हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद संबंधों ने जो गति पकड़ी, उसे देखते हुए इस दौर को 'स्वर्णिम काल' कहा जाने लगा। चूंकि हसीना की विदाई के बाद बांग्लादेशी राजनीति की रंगत बदल गई है, इसलिए भारत को भी नई वास्तविकताओं के अनुरूप नए सिरे से कदम बढ़ाने होंगे। असल में यह बदला हुआ रुझान ही दक्षिण एशिया की इस महत्वपूर्ण साझेदारी को भारी दबाव में डाल रहा है। बांग्लादेश में अंतरिम प्रशासन के भीतर भारत-विरोधी प्रलाप जोर पकड़ रहा है, जिससे सरकारों के स्तर पर रचनात्मक सक्रियता के लिए अनुकूल परिवेश नहीं बन पा रहा है। हिंदुओं और उनके उपासन स्थलों पर बढ़ते हमलों ने भी दोनों देशों में इंटरनेट मीडिया को लड़ाई का एक नया अखाड़ा बना दिया है। इसका से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी ने द्विपक्षीय संबंधों की हवा और बिगाड़ दी है। त्रिपुरा में बांग्लादेश कांउसलेट प्रकरण में इसकी प्रतिक्रिया भी दिखी। दोनों देशों के इंटरनेट मीडिया महारथियों ने भी राजनयिकों की गिरफ्तारी बढ़ा दी हैं। जहां बांग्लादेश का घरेलू माहौल भारत के लिए चिंतित करने वाला पहलू है, वहीं भारत में शेख हसीना की मौजूदगी बांग्लादेश की आर्थिकी को लेकर रही है, जिन्हें देश में वापस लाकर उन पर तरह-तरह के मुकदमे चलाने की मांग तेजी से जोर पकड़ती जा रही है।

पिछले कुछ महीनों में घरेलू राजनीतिक माहौल जिस तरह से रिश्तों की धुरी को प्रभावित करने में लगा है, उसे देखते हुए विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हुआ। इस दौरान आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग, ऊर्जा के स्तर समन्वय एवं सक्रियता, सीमा प्रबंधन और विकास से जुड़ी गतिविधियों पर सहयोग जैसे अहम मुद्दे फिर से चर्चा के केंद्र में आए। इन मुद्दों के न केवल द्विपक्षीय संबंधों, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय समीकरणों की दृष्टि से भी गहरे निहितार्थ हैं। ऐसे में, नई दिल्ली ने ढाका से संपर्क साधकर उचित ही किया और अब यह बांग्लादेश की नई सरकार के ऊपर है कि वह इस पहल पर सार्थक रूप से प्रतिक्रिया जताए और अनुकूल कदम उठाए।

बांग्लादेश कई चुनौतियों से जूझ रहा है और अंतरिम सरकार महीनों के बाद भी अपेक्षित स्थिरता नहीं दे पाई है। एक समय बांग्लादेश की आर्थिकी को लेकर तमाम उम्मीदें लगाई जा रही थीं। अब उनपर ग्रहण लगता दिख रहा है। शासन-प्रशासन का पूरा ढांचा लड़खड़ा गया है और उसके लिए केवल भारत को दोष देने से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। बांग्लादेश के समक्ष इस समय सबसे बड़ा संकट यही है कि यदि राजनीतिक नेतृत्व ने कारगर कदम नहीं उठाए तो न केवल हाल की सभी उपलब्धियां धूल-धूसरित हो जाएंगी, बल्कि भविष्य को लेकर भी नए सवाल उठ खड़े होंगे। यह अफसोस की बात है कि सत्ता प्रतिष्ठान की कमान संभालने वाले कुछ शीर्ष लोग उस पाकिस्तान को अपने साथी के रूप में देख रहे हैं, जिसके दिए घावों से शायद बांग्लादेश का अंतस अभी तक कराह रहा होगा। यह भी शुभ संकेत नहीं है कि बांग्लादेश के पितामह कहे जाने वाले शेख मुजीब की विरासत को किनारे करने और उसे दबाने की कोशिश की जा रही है।

हसीना के शासन में भारत-बांग्लादेश संबंध सही दिशा में आगे बढ़ने लगे थे। आर्थिक संबंधों पर उनके फोकस ने ऊर्जा, कनेक्टिविटी और सीमा प्रबंधन के स्तर पर व्यापक साझेदारी का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि उस दौर को भी निर्बाध एवं मुश्किलों से मुक्त कहना सही नहीं होगा। सीमा सुरक्षा, नदी जल समझौतों और पलायन जैसे मुद्दे अनसुलझे एवं विवादित बने रहे। साथ ही, हसीना भारत और चीन को लेकर भी संतुलन का रुख अपनाती रहीं। चीन उनके दौर में ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा सामरिक साझेदार बना। इसके बावजूद भारत के साथ भी उनके संबंध सही दिशा में इसलिए बढ़ते गए, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक विश्वास की बुनियाद पर काम करने को तरजीह दी और एक दूसरे की चिंताओं को समझकर कदम उठाए। यह दृष्टिकोण उपयोगी सिद्ध हुआ।

यूनुस सरकार के स्तर पर तमाम चुनौतियां उत्पन्न होने के बावजूद नई दिल्ली ने यही संकेत दिए हैं कि वह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। हालांकि, ऐसी तत्परता तभी फलीभूत हो सकती है कि जब दूसरा पक्ष भी संकीर्ण राजनीतिक हितों एवं तात्कालिक लाभ से परे व्यापक हितों को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हो। भौगोलिक नियति यही निर्धारित करती है कि साझा सीमा, संस्कृति एवं भौतिक परस्पर निर्भरता के आधार पर भारत एवं बांग्लादेश ऐसे स्वाभाविक साझेदार हैं, जो घरेलू राजनीतिक बंदिशों से परे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि द्विपक्षीय संबंधों में आगे की राह पथरीली लग रही है, लेकिन इन दोनों पड़ोसियों को इससे पार पाने की कोई युक्ति खोजनी ही होगी, क्योंकि दक्षिण एशिया के भविष्य की बुनियाद नई दिल्ली-ढाका धुरी पर टिकी हुई है।

(लेखक ओआरओ रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

गुकेश ने किया छोटी उम्र में बड़ा कमाल

विशाल सरीन

शतरंज का विश्व चैंपियन बनकर गुकेश ने वह कर दिखाया है, जो इसके पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया

देश का नया अंतरराष्ट्रीय खेल सितारा। एएचपी

डोम्माराजू गुकेश का महज 18 साल की उम्र में शतरंज का विश्व चैंपियन बनना देश के लिए एक ऐसी शानदार उपलब्धि है, जो इसके पहले किसी भारतीय खिलाड़ी ने किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल में अर्जित नहीं की। गुकेश की यह उपलब्धि इसलिए अभूतपूर्व हो जाती है कि विश्वनाथन आनंद जब विश्व चैंपियन बने थे तो वह करीब 31 साल के थे। आनंद ने 2013 में जब अपना खिताब गंवाया, तब गुकेश ने शतरंज खेलना शुरू ही किया था। वह 2019 में 12 साल सात माह की आयु में दूसरे सबसे युवा ग्रैंडमास्टर बन गए थे। इसके चार साल के अंदर वह विश्व चैंपियन बन गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। गुकेश जब ग्रैंडमास्टर नहीं बने थे, तभी उन्होंने कहा था कि मैं सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनना चाहता हूं। आखिरकार सिंगापुर में उन्होंने यह कर दिखाया और अपने बचपन के सपने को साकार किया। उन्होंने चैंपियन बनने के लिए केवल सपने ही नहीं देखे, बल्कि उनकी पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्न भी किए। इसमें उनके माता-पिता का भी भरपूर योगदान रहा, जिन्होंने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए जो कुछ संभव था, किया। एक समय तो डाक्टर पिता ने नौकरी भी छोड़ दी थी।

गुकेश की सफलता की महत्ता इसलिए कहीं अधिक है, क्योंकि उनके पहले विश्व में कोई भी इतनी कम उम्र में शतरंज का विश्व चैंपियन नहीं बना। उनके पहले गैरी कास्परोव शतरंज के युवा विश्व चैंपियन थे। जब गैरी विश्व चैंपियन बने थे, तब उनकी उम्र 22 साल सात महीने थी। गुकेश ने इतिहास रच दिया। इसी कारण उनकी गिनती कम उम्र में करिश्मा करने वाले दुनिया भर के अन्य खिलाड़ियों से की जा रही है। गुकेश की सफलता ओलिंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने जैसी है। यहां यह ध्यान रहे कि जेवलिन थ्रो शतरंज के मुकाबले कम ही देशों में प्रचलित है। छोटी उम्र में बड़ा कमाल करने वाले गुकेश को पुरस्कार राशि के रूप में 1.35 मिलियन डालर यानें करीब 11.45 करोड़ रुपये मिलेंगे। सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप की कुल पुरस्कार राशि 2.5 मिलियन डालर (21.2 करोड़ रुपये) थी। यह भारी भरकम राशि शतरंज की लोकप्रियता बयान करती है। भारत और विशेष रूप से उत्तर भारत में शतरंज भले ही उतना लोकप्रिय खेल न हो, लेकिन यह फुटबाल के बाद दुनिया का दूसरा लोकप्रिय खेल है। यह करीब 200 देशों में खेला जाता है। चूंकि अब गुकेश के रूप में भारत के पास सफलता की एक बड़ी गाथा है, इसलिए देश में इस खेल की लोकप्रियता बढ़ने के और अधिक आसार हैं। सबसेस स्टोरी हर किसी और खासकर बच्चों एवं युवाओं को प्रेरणा प्रदान करती है। शतरंज के बारे में कहा जाता है कि इसका आविष्कार भारत में हुआ। हाल के समय में गुकेश, अर्जुन एरिगैसी, पी. हरिकृष्णा, आर. प्रगनानंद, बिदित गुजराती आदि ने यह दिखाया है कि शतरंज फिर से भारत में जड़ें जमा रहा है। इसकी पुष्टि तब भी हुई थी, जब भारत ने हाल में शतरंज ओलिंपियाड में स्वर्ण पदक जीता था।

18 साल के गुकेश ने 32 साल के चीनी खिलाड़ी और गत चैंपियन डिंग लिरेन को 6.5 के मुकाबले 7.5 के स्कोर से हराया। हालांकि वह अपना पहला मुकाबला हार गए थे, लेकिन तीसरी बाजी वह अपने नाम करने में सफल रहे। इसके बाद दोनों ग्रैंडमास्टरों ने सात मुकाबले ड्रा खेले। फिर 11वां मुकाबला गुकेश ने जीता। इसके बाद 12 वां मुकाबला चौनी ग्रैंडमास्टर ने जीत लिया। 13 वीं बाजी फिर ड्रा रही। 14 वीं बाजी गुकेश ने जीतकर खिताब अपने नाम किया। यदि यह बाजी भी ड्रा रहती तो जीत का फैसला टाईब्रेकर से होता। बेस्ट आफ 14 फार्मेट में जीत हासिल करने वाले गुकेश तीसरे ग्रैंडमास्टर रहे। उनके पहले डिंग लिरेन और मैग्नस कार्लसन भी ऐस कर चुके हैं। दोनों ग्रैंडमास्टरों के बीच कांटे की टक्कर ने यह दिखाया कि चौनी खिलाड़ी को कमतर करके नहीं आंका जा सकता।

शतरंज के खेल में धैर्य और मानसिक दृढ़ता बहुत मायने रखती है और गुकेश ने यह साबित किया कि इतने कम उम्र में वह मानसिक रूप से कहीं अधिक मजबूत हैं। यही मजबूती उनकी सफलता का कारण बनी। उनकी सफलता के पीछे उनकी खुद की लगन और मेहनत तो रही ही, उनकी टीम का सपोर्ट भी रहा। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद भले ही उनकी टीम का हिस्सा न हों, लेकिन वह अन्य भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की तरह उनके भी प्रेरणास्रोत हैं। गुकेश विश्वनाथन आनंद की चेस अकादमी वेस्टब्रिज का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने शतरंज के कई गुर उनसे भी सीखे हैं। जैसे आनंद की कामयाबी ने भारत में तमाम खिलाड़ियों को शतरंज में कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित किया, वैसे ही यह काम अब गुकेश भी करने वाले हैं और शायद कहीं अधिक प्रभावी ढंग से, क्योंकि उन्होंने वह हासिल किया, जो पहले किसी ने नहीं किया। गुकेश ने अपनी प्रतिभा का परिचय बचपन में ही दे दिया था, लेकिन उनका हालिया सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। गुकेश डिंग लिरेन को चुनौती देने में इसलिए सक्षम हो सके, क्योंकि वह वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का टोरंटो में आयोजित आखिरी चेस टूर्नामेंट कैंडिडेट्स तब जीतने में सफल रहे थे, जब इसके आसार कम दिख रहे थे। गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए इसलिए क्वालीफाई कर सके थे, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में चेन्नई में सुपर ग्रैंडमास्टर टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट हो गुकेश को टोरंटो तक ले जाने में सहायक बना। शतरंज में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि देश में अंतरराष्ट्रीय चेस टूर्नामेंट आयोजित होते रहें।

(लेखक चेस इंटरनेशनल मास्टर एवं फिडे सीनियर ट्रेनर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मबोध

सामान्यतः एक समझे जाने वाले आत्मज्ञान और आत्मबोध में प्रभूत अंतर है। बौद्धिक दक्षता से बाह्य जानकारियों का संग्रहण ज्ञान कहलाता है, जबकि बोध आत्मस्फूर्त ज्ञान का पवित्रतम रूप है। इसमें संसरकिय प्रपंच का स्पर्श भी नहीं होता जो चिंतन, वाणी एवं कर्म सभी को पवित्र कर परम आनंद की प्राप्ति कराता है। संसार में ज्ञान का दुरुपयोग तो देखा जाता है, पर बोध केवल मंगलकारी होता है। अतएव ज्ञान तब तक सर्वथ नहीं होता, जब तक बोध का विषय न बने। यद्यपि ज्ञान और बोध दोनों बुद्धिलब्ध हैं, किंतु सांसारिक माया के वशीभूत होकर स्वार्थ एवं लोभ से प्रेरित बुद्धि आत्मबोध नहीं कर पाती। हालांकि माया का आवरण हटने से समत्व बुद्धि से अर्जित ज्ञान बोध को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए आत्मबोध को जागरण काल कहा जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म से ही जगत की वास्तविकता का बोध था। उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने गृह त्यग दिया। मानव की दुखनिवृत्ति हेतु उनका संकल्प और दृढ़ हो गया जो आत्मबोध का परिणाम था।

'आत्मा सबसे बड़ा शिक्षक है।' स्वामी विवेकानंद का यह कथन आत्मबोध का मर्म उजागर करता है। उससे प्राप्त ज्ञान आत्मबोध का ही उद्गारण है। विकार शून्य होने से उसमें बाह्य एवं आंतरिक भेद नहीं होते। आदि शंकराचार्य जी का आत्मबोध तो इतना प्रबल था कि प्रथम दर्शन में ही वह गुरु के समक्ष अपने परिचय में कहते हैं, 'गुरुदेव! मैं मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और प्राण नहीं हूं। शरीर का संचालक इंद्रिय समूह भी नहीं हूं। राग-द्वेष, जाति-भेद से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं बंधन भी नहीं और मुक्त भी नहीं। इसलिए इस जग में मेरे माता-पिता, बंधु-बांधव, गुरु-शिष्य कोई नहीं हैं। मैं निराकार, सर्वव्यापी एवं आनंद स्वरूप सच्चाइ शिव हूं।' आत्मबोध परमात्म तत्व की मंगल ध्वनि होती है जो भेद बुद्धि को समाप्त कर जगत में समत्व भाव का विस्तार करती है।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

पुरुषों की समस्याओं की अनदेखी

सोनम लववंशी

एक प्रतिभाशाली इंजीनियर अतुल सुभाष को आत्महत्या की घटना ने न केवल समाज को झकझोर दिया है, बल्कि पुरुष प्रताड़न और उनसे जुड़े मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को बहस के केंद्र में ला दिया है। अतुल ने घरेलू प्रताड़न और न्यायिक पक्षपात से तंग आकर अपनी जान दे दी। अतुल के 24 पन्नों के सुसाइड नोट और 90 मिनट के वीडियो ने उनकी पीड़ा और समाज की उदासीनता को उजागर किया है। यह घटना हमारे समाज में गहरे बैठे पूर्वाग्रहों और पुरुषों की समस्याओं को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। समाज ने महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए सशक्त कानून बनाए हैं, लेकिन पुरुषों की समस्याओं को गंभीरता से लेने का प्रयास अब तक नहीं किया गया। जो दुखद और किसी त्रासदी से कम नहीं है।

महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय और हिंसा को रोकने के लिए कानून आवश्यक हैं, लेकिन इन कानूनों के दुरुपयोग के कारण निर्दोष पुरुषों को जो मानसिक और सामाजिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, उसे नकारा नहीं जा सकता। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में 1.64 लाख आत्महत्याओं में से 81,063 विवाहित पुरुष थे, जबकि विवाहित महिलाओं की संख्या 28,680 थी। ये आंकड़े पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। समाज में पुरुषों को 'मजबूत' और 'सक्षम' मानने की रूढ़िवादी धारणा ने उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से वंचित कर दिया है। बचपन से ही लड़कों को 'लड़के रोते नहीं हैं' जैसे ताने सुनाए जाते हैं, जिससे वे अपनी भावनाओं को दबाने की आदत डाल लेते हैं। यही भावनात्मक दमन समय के साथ मानसिक अवसाद और अंततः आत्महत्या जैसे गंभीर कदमों का कारण बनता है।

> समाज ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सशक्त कानून बनाए हैं, लेकिन पुरुषों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेता है

498-ए जैसे कानून, जो मूल रूप से महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाए गए थे, का दुरुपयोग भी पुरुषों के उत्पीड़न का एक बड़ा कारण है। अमेरिका के कानून से प्रेरित यह प्रविधान वहां जेंडर-निरपेक्ष है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के उत्पीड़न के मामलों को समान दृष्टि से देखता है। इसके विपरीत, भारत में इसको जेंडर-विशिष्ट बनाया गया है, जिससे पुरुषों के लिए न्याय प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इस असंतुलन ने पुरुषों में न केवल हताशा बढ़ाई है, बल्कि उनकी आत्महत्या की दर को भी बढ़ाया है। एक आंकड़े के अनुसार पुरुषों की आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में दो गुनी है। इसका एक प्रमुख कारण समाज का पुरुषों को अपनी समस्याओं के साथ अकेला छोड़ देना है। अतुल सुभाष का मामला हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

समानता के लिए हों समन्वित प्रयास

'विशेषाधिकार वाली मानसिकता का सामना' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में शंकर शरण ने विशेषाधिकारवादी मानसिकता की आलोचना करते हुए इस प्रवृत्ति को समाज में असामानता और विभाजन का कारण बताया है। उन्होंने सामाजिक समरसता स्थापित करने और सभी वर्गों को समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। विशेषाधिकार की मानसिकता समाज में विषमता एवं असंतोष का बीज बोती है। यह समस्या उस सोच से उपजती है, जहां कुछ वर्ग अपने अधिकारों को जन्मसिद्ध मानते हैं, जबकि बाकी समाज हाशिए पर छूट जाता है। यह मानसिकता न केवल सामाजिक संतुलन को बिगाड़ती है, बल्कि देश के विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है। यदि हम स्थानीय स्तर पर देखें तो कई बार सरकारी योजनाएं केवल एक वर्ग विशेष तक सीमित रह जाती हैं। इस समस्या का समाधान 'समावेशी सोच' में है। अधिकार और जिम्मेदारी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई विशेष वर्ग संसाधनों पर प्राथमिकता चाहता है, तो उसे उन संसाधनों के संरक्षण और साझा उपयोग के लिए भी कदम उठाने चाहिए। सरकार और समाज को मिलकर ऐसे योजनाएं बनानी होंगी, जो जरूरतमंदों तक पहुंचें, न कि केवल प्रभावशाली वर्ग तक। समाज में विशेषाधिकार और समानता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक नए सोच की आवश्यकता है, जो समरसता, न्याय और सहभागिता के मूल्यों को आत्मसात करे।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

विपक्षी गठबंधन

'बिखराव की और जाता विपक्षी गठबंधन' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में कैसी त्यागी ने मात्र नरेन्द्र मोदी या भाजपा विरोध की भावना से पनपे विपक्षी 'इंडी गठबंधन' की भीतरी लड़ाई और टूटने की प्रक्रिया पर सही प्रकाश डाला है। जिस गठबंधन की बुनियाद बिना किसी समान विचारधारा या नीति निर्देशक सिद्धांतों के रखी गई हो, उसका ये हश्र होना ही है। इनमें से अधिकांश घटक दलों की स्थापना कांग्रेस की नीतियों या कांग्रेस के नेताओं के विरोध के कारण हुई थी और कई वर्षों तक उन्होंने सड़कों पर कांग्रेस का प्रखर विरोध किया। चाहे शिवसेना, राकांपा, आम आदमी पार्टी, राजद, वाम मोर्चा, द्रमुक हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर इंडी गठबंधन के नेतृत्व की लालसा रखने वाली ममता दीदी हों, इन सबका मूल चरित्र अगर समान था तो सिर्फ कांग्रेसी विचारधारा का विरोध था और आज ये सब उसी कांग्रेस के नेतृत्व में कैसे एकजुट रह सकते हैं। शायद इनके संस्थापक सदस्यों के आत्मा उनको जरूर कचोटता होगा। न ही देश के विकास के लिए कोई समान सोच इन विपक्षी दलों के पास है न ही कोई दूरदृष्टि प्रतीत होती है। सिवाय संकुचित क्षेत्रीय सोच और सम-दाम-दंड भेद द्वारा सत्ता पाने की लालसा के। तो ऐसे में विपक्षी गठबंधन का बिखराव तो निश्चित है।

पीयूष शंकर गर्ग, शिक्षा सन्सिटी, गाजियाबाद

शतरंज के नए सम्राट

भारत सिर्फ शतरंज का जन्मदाता ही नहीं है, बल्कि भारत ने विश्व को सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन भी दे दिया। 12 दिसंबर सिंगापुर में भारतीयों के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया, भारत के डी गुकेश ने मात्र 18 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बनकर उपलब्धि हासिल की। गुकेश की जीत ने उन्हें विश्वनाथ आनंद के बाद शतरंज विश्व चैंपियन जीतने वाले दूसरे भारतीय के रूप में स्थापित कर दिया। युवा ग्रैंडमास्टर की रणनीतिक कौशल और प्रतिभा ने उन्हें डिंग लिरेन की गलती का फायदा उठाने में सक्षम बनाया, जिससे उन्हें ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। गुकेश की जीत न केवल उनके शतरंज कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन था, बल्कि उनके लिए एक भावात्मक पल भी था, वह इस अद्भुत पल पर भावुक हो गए, अपने लंबे समय से संजोए गए सपने के सकार होने का अहसास होने पर उनके आंसू बहना स्वाभाविक था।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। अपना मत व पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 257

मांग और आपूर्ति में विसंगति

देश के शहरों में किफायती आवास की स्थिति बदतर होती जा रही है। हाल के वर्षों में किफायती श्रेणी के मकानों की मांग काफी कम हुई है क्योंकि इनका संभावित खरीदार वर्ग महामारी से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके अलावा आवास ऋण की ब्याज दरों और आवासीय कीमतों में भारी इजाफे ने भी कम आय वाले परिवारों के लिए हालात मुश्किल बना दिए हैं। यही वजह है कि किफायती आवास की बिक्री में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई है। महामारी के कारण व्याप्त निराशा और निर्माण तथा श्रमिकों की बढ़ती लागत ने अचल संपत्ति डेवलपरों को विवश किया कि वे अपना ध्यान किफायती मकानों से दूर प्रीमियम और लक्जरी श्रेणी के मकानों पर लगाएं। इन कारणों से मांग और आपूर्ति का अंतर उत्पन्न हो गया है जो किफायती आवासीय इकाइयों को प्रभावित कर रहा है। नाइट फ्रैंक और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया एक हालिया अध्ययन बताता है कि यह समस्या वास्तव में कितनी विकट है।

अध्ययन दिखाता है कि 2030 तक देश में 3.12 करोड़ किफायती मकानों की कमी हो जाएगी। एक करोड़ से अधिक मकानों की कमी पहले ही बनी हुई है। यह इस बात की ओर भी संकेत करता है कि किफायती श्रेणी के मकानों की बिक्री कम हुई है। वर्ष 2018 में जहां देश के आठ प्रमुख शहरों में सभी आवासों की बिक्री में 54 फीसदी किफायती श्रेणी में थे, वहीं 2024 में यह हिस्सेदारी कम होकर 26 फीसदी रह गई। बढ़ते शहरीकरण, आय के स्तर में बेहतरी और अर्थव्यवस्था के औपचारिक होने जैसे सकारात्मक घटनाक्रम के बावजूद ऐसा हो रहा है। जबकि ये कारण आवास बाजार को मजबूत बनाने वाले हैं। देश में किफायती आवास की अपर्याप्त आपूर्ति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में किफायती श्रेणी के आवास की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है जिसने समस्या को और गंभीर बना दिया है। उदाहरण के लिए अध्ययन बताते हैं कि 2019 और 2024 के बीच मुंबई महानगर क्षेत्र में 30 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाली आवासीय इकाइयों की औसत लॉन्च कीमत आठ फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) की दर से बढ़ीं, जबकि 60 से 160 वर्ग मीटर वाली आवासीय इकाइयों की कीमतों में 4.4 फीसदी सीएजीआर की दर से इजाफा हुआ। परियोजनाओं का वित्तीय दृष्टि से अव्यावहारिक होना, किफायती जमीन की उपलब्धता की कमी और डेवलपरों एवं संभावित खरीदार दोनों की ऋण पर अत्यधिक निर्भरता भी बाधा है।

मकानों की ऊंची कीमतें अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं। इससे शहरी इलाकों में काम करने वालों के वेतन का प्रीमियम खत्म होता है और नियोक्ताओं के लिए प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखना मुश्किल होता है। आपूर्ति की कमी होने के कारण अमीर रियल एस्टेट डेवलपर और एजेंट तंग बाजार का फायदा उठाते हैं। किरायेदारों से जमकर मुनाफा कमाया जाता है और पहली बार मकान खरीदने वाले पीछे छूट जाते हैं। इस संदर्भ में आवास बाजार के संचालन में मजबूत योजना का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। सरकारी नीतियां मसलन प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय शहरी किराया आवास नीति शायद पर्याप्त साबित न हों। नए सैटेलाइट शहर विकसित करना और इन क्षेत्रों में भौतिक अधोसंरचना की कमियों को दूर करना आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कर सकता है और बड़े शहरों पर से दबाव कम कर सकता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास बनाना, ऊंचे फ्लोर एरिया अनुपात के साथ जमीन का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित करना तथा मकान खरीदने वालों तथा डेवलपरों को पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराना भी समस्याओं को काफी हद तक कम करेगा। एक अन्य संभावित हल विभिन्न सरकारी उपक्रमों तथा राज्य सरकारों के नियंत्रण वाली खाली जमीन का इस्तेमाल करना भी हो सकता है।

विनय सिन्हा

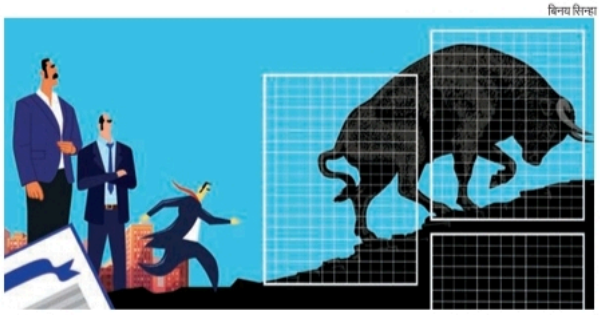

अमेरिकी बाजारों में तेजी और बाकी दुनिया

विश्व के अन्य देशों और बाजारों के मुकाबले अमेरिकी शेयरों में तेजी का दौर लगातार चलता आ रहा है, परंतु कभी न कभी तो यह स्थिति बदलेगी। बता रहे हैं आकाश प्रकाश

अमेरिका के शेयर बाजारों पर विभिन्न बाजार पर्यवेक्षकों के आलेखों और टिप्पणियों की बाढ़ देखने को मिली। लगभग उन सभी का मानना था कि वह इकलौता ऐसा बाजार है जहां निवेश करना सही है। इनमें से अधिकांश बाजार पर्यवेक्षकों का मानना है कि अमेरिकी बाजार अपनी तेजी के उच्चतम स्तर पर हैं। यह सहमति इतनी तगड़ी है कि अमेरिका तथा दुनिया के अन्य हिस्सों के निवेशकों ने भी उभरते बाजारों जैसे अन्य क्षेत्रों पर नजर तक डालनी बंद कर दी है। उभरते बाजार वर्ग के सामने फिलहाल गंभीर चुनौतियां हैं और वे प्रासंगिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ष 2025 के लिए अधिकांश वैश्विक पूर्वानुमान यही मान रहे हैं कि अमेरिका इकलौता ऐसा बाजार है जिस पर समय और धन लगाया जाए। आंकड़ों पर नजर डालें तो यह देखना आसान है कि आखिर क्यों हर कोई अमेरिका को लेकर सकारात्मक है और क्यों विरोधी अमेरिकी परिसंपत्तियों को लेकर सकारात्मकता के प्रति इतने असहज हैं। बीते वर्षों के दौरान अमेरिकी शेयरों ने अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों में उभरते बाजारों के शेयरों को पीछे छोड़ दिया है। खासतौर पर 2008 में वित्तीय संकट के बाद। वर्ष 2010 के आरंभ से 2024 के अंत तक के 15 साल में अमेरिकी बाजारों ने एमएससीआई वर्ल्ड इक्विटीज को 14 साल पछाड़ा। केवल 2017 अपवाद रहा। बीते एक दशक में एसऐंडपी 500 ने यूरोपीय शेयरों को सालाना 7.7 फीसदी की दर से और उभरते बाजारों के शेयरों को सालाना 9.7 फीसदी पीछे छोड़ा है।

आज एमएससीआई वर्ल्ड इक्विटी सूचकांक में अमेरिका 67 फीसदी का हिस्सेदार है यानी अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत दुनिया के अन्य बाजारों के संयुक्त भार से दोगुना भार रखता है। अगला बड़ा बाजार जापान है जो सूचकांक में पांच फीसदी हिस्सेदारी रखता है। दुनिया में कहीं भी वैश्विक शेयरों पर होने वाली चर्चा में 90 फीसदी से अधिक समय अमेरिका पर खर्च किया जाता है। यह इकलौता बाजार है जो मायने रखता हुआ नजर आता है। अन्य सभी बाजार और वैश्विक रुझान अमेरिका केंद्रित हैं। अमेरिकी शेयर वैश्विक शेयरों की तुलना में रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। ऐसा केवल ऐपल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल की मातृ कंपनी अल्फाबेट, एमेजॉन, एनवीडिया, मेटा और टेस्ला जैसी सात बड़ी कंपनियों की बदौलत नहीं है। अगर हम इन्हें छोड़कर एसऐंडपी की शेष 493 कंपनियों की बात करें और उनकी तुलना यूरोपीय संघ के शेयरों से करें तो अमेरिकी कंपनियों को हर क्षेत्र में मूल्यांकन में बढ़त हासिल है। मूल्यांकन प्रीमियम का संबंध शेयरों पर उच्च प्रतिफल से है। बहरहाल, हमेशा ऐसा नहीं था। अमेरिकी शेयरों के पक्ष में यह स्थिति वैश्विक वित्तीय संकट के बाद निर्मित हुई। संकट मोटे तौर पर अमेरिका में केंद्रित था और आक्रामक तथा तीव्र नीतिगत प्रयासों के माध्यम से अमेरिका ने मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करते हुए समस्या से पार पाया।

अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो संकट के ऐन पहले यानी 2007 के आखिर तक व्यापक यूरोप का बाजार पूंजीकरण और वैश्विक सूचकांकों पर भार अमेरिका से अधिक था। वर्ष 2002 से 2009 तक आठ साल की अवधि संकट की ओर ले गई। एमएससीआई वर्ल्ड ने आठ में से सात सालों में एसऐंडपी को पीछे छोड़ दिया। आज कल्पना करना मुश्किल है लेकिन 1989 में वैश्विक सूचकांकों में जापान का भार अमेरिका से अधिक था। वह दुनिया का सबसे मूल्यवान और महंगा बाजार था।

अमेरिका जहां दीर्घकालिक प्रतिफल के मामले में सभी प्रमुख शेयर बाजारों में बेहतर रहा, वहीं करीब 7 फीसदी की वास्तविक वृद्धि दर के साथ वह कभी भी एकतरफा रुझान का विषय नहीं रहा। पांच साल या उससे लंबी अवधि ऐसी भी रही जब वह वैश्विक बाजारों में पीछे रहा। हालात हमेशा आज जैसे नहीं रहे। विगत 15 साल के शानदार प्रदर्शन के साथ अब अमेरिकी मूल्यांकन रिकॉर्ड स्तर पर हैं। रुझान संकेतकों की भी बात करें तो पेशेवर फंड प्रबंधकों सहित किसी भी सर्वे में अमेरिकी बाजारों की तेजी इससे ऊंचे स्तर पर नहीं रही है।

खुदरा रुझान संकेतक भी तकरीबन अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं और खुदरा आवक भी शायद ही कभी इससे ऊंचे स्तर पर रही हो। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी सहित बाजार और परिसंपत्तियों का एक हिस्सा ऐसा है जो अभी भी अटकलबाजी में लिप्त नजर आ रहा है। वर्ष 2008 के बाद अमेरिकी शेयरों में बेहतरीन तेजी देखने को मिली। रुझान और मूल्यांकन दोनों ही मोर्चों पर शायद ही कभी इससे अधिक तेजी देखने को मिली हो। इस बात पर सहमति है कि अमेरिका के विरुद्ध दांव लगाना उचित नहीं और वैश्विक सूचकांकों में भार के मामले में भी वह अब तक के उच्चतम स्तर के करीब है। मैं इस नजरिये के साथ हूं कि व्यक्तिगत निवेशकों या प्रोपराइटरी पूंजी का प्रबंधन कर रहे किसी भी व्यक्ति के लिए यह बात समझदारी भरी है कि अमेरिका को कम महत्त्व देते हुए गति को धीमा करे। अमेरिका इक्विटी ऐसेट में उच्चतम स्तर पर है और उसके प्रदर्शन में देर सबेर धीमापन आएगा। एक रणनीतिक कदम के रूप में यह बहुत सहज संभव है कि अमेरिका पांच साल तक वैश्विक स्तर पर कमजोर प्रदर्शन करे। मूल्यांकन के मौजूदा बिंदुओं को देखते हुए क्या अमेरिका आने वाले दिनों में अन्य बाजारों से पीछे भी रह सकता है? यकीनन ऐसा हो सकता है। उभरते बाजार और यूरोप दोनों की वापसी संभव है। लंबी अवधि में अमेरिका ने सबसे अच्छा प्रतिफल दिया है और किसी भी वैश्विक इक्विटी आवंटन में वह मूल में रहेगा। नवाचार और प्रौद्योगिकी में उसकी बढ़त बहुत ज्यादा है और मुनाफे पर उसका ध्यान इतना अधिक है कि उसकी आय वृद्धि दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से से अधिक ही रहेगी।

संस्थागत निवेशकों के लिए निर्णय अधिक कठिन है। सक्रिय धन-प्रबंधन की खतरनाक प्रवृत्ति को देखते हुए अधिकांश फंड कमजोर प्रदर्शन को बरदाश्त नहीं कर सकते हैं जिसकी गारंटी अमेरिका को कम करके आंकने से मिल जाएगी। इनमें से कई फंड बीते पांच सालों से अमेरिकी शेयरों से दूरी बनाने की वकालत कर रहे हैं और वे पूरी तरह गलत साबित हुए। ऐसे में वे दोबारा उसे दोहराना नहीं चाहते।

अमेरिकी बाजारों का कमजोर प्रदर्शन कब शुरू होगा इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। अमेरिका हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करता रह सकता है। वह वैश्विक सूचकांकों में 80-85 फीसदी का हिस्सेदारी नहीं हो सकता। यह स्थिति जरूर बदलेगी। बस यह अनुमान लगाना कठिन है कि ऐसा कब होगा।

ऐसे हालात में अपने धन का प्रबंधन और अपने प्रति जवाबदेह होते हुए जोखिम लेना आसान होता है। अधिकांश संस्थागत निवेशकों के पास लंबे समय तक कमजोर प्रदर्शन को झेलने की क्षमता नहीं होती। वे परिभाषा के स्तर पर अमेरिकी बाजारों से दूर जाने में देर कर देंगे।

(लेखक अग्मांसा कैपिटल से जुड़े हैं)

अदाणी मामला और भारत के समक्ष अवसर

अमेरिका के न्याय विभाग और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने गौतम अदाणी, उनके भतीजे सागर अदाणी और छह अन्य लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारत में अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी और इस बात को अमेरिकी निवेशकों से छिपाया। इन आरोपों से इनकार किया गया है और कहा गया है कि रिश्वत देने के प्रमाण ही नहीं हैं।

अभी दो वर्ष भी नहीं हुए जब न्यूयॉर्क की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अदाणी समूह पर आरोप लगाए थे। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अदाणी समूह पर शेयरों के साथ छेड़छाड़ करने और बहीखातों में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि समूह ने विदेशी रकम का इस्तेमाल कर अपना बाजार मूल्य बढ़ा कर दिखाया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने समूह के सौदों और लेनदेन की जांच की मगर उसे गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। सेबी ने हिंडनबर्ग को ही कठघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि इस शॉर्ट सेलर फर्म की जांच की जा रही है क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट में मौजूद उस जानकारी का इस्तेमाल कर शेयरों की खरीदफरोख्त की, जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं थी।

इन आरोपों के कारण बाजार में काफी उतार-चढ़ाव आया और निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति एम एल शर्मा के नेतृत्व में एक समिति का गठन यह पता लगाने के लिए किया कि इसमें कोई नियामकीय नाकामी तो नहीं थी। समिति ने जांच के कई पहलुओं पर अदाणी को पाक साफ नहीं करार दिया लेकिन उसने कहा कि 'अब तक' समूह के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। समिति ने पाया कि अदाणी कंपनियों की जांच में बतौर नियामक सेबी की कोई नाकामी नहीं थी।

हिंडनबर्ग के आरोप अधिक गंभीर थे मगर इस बार के आरोप अधिक विश्वसनीय स्रोत से आए हैं और उनके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। परंतु तथ्यों और परिणामों को छोड़ दें तो भी इन आरोपों ने देश में कारोबार करने की मूल भावना को ठेस पहुंचा दी है। पिछले कई सालों में भारत को 'चीन प्लस वन' नीति का फायदा मिला है। इस नीति के तहत कंपनियां चीन में विनिर्माण जारी रखती हैं मगर भारत समेत अन्य अर्थव्यवस्थाओं की ठोह भी लेती हैं ताकि उन्हें विनिर्माण का वैकल्पिक केंद्र बनाकर आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाई जा सके। इस नीति को कोविड-19 महामारी के दौरान बल मिला जब महसूस हुआ कि विनिर्माण और माल की आवाजाही के लिए एक ही देश पर निर्भर रहना कितना जोखिम भरा है।

इस चलन को बढ़ावा मिला क्योंकि कंपनियां उन चुनौतियों से निपटने के तरीके तलाशने लगीं, जो उनकी आपूर्ति श्रृंखला में आ सकती थीं। ये चुनौतियां चीन-अमेरिका तनाव जैसे भू-राजनीतिक जोखिमों और दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध तथा चीनी माल पर शुल्क के कारण आ सकती हैं। चीन में महंगी होती मजदूरी ने भी कारोबारियों को किफायती जगह खोजने पर मजबूर किया है।

निवेश के लिहाज से भारत में जबरदस्त संभावनाएं हैं मगर धारणा यही बनी हुई है कि हाल-फिलहाल हुई सारी प्रगति के बाद भी भारत चीन का स्थान नहीं ले सकता - कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं। चीन के पास भारी-भरकम बुनियादी ढांचा है, प्रौद्योगिकी में उसकी ताकत से पूरी दुनिया जलती है और उसके पास बेहद एकीकृत आपूर्ति व्यवस्था है। उसने विनिर्माण प्रौद्योगिकी में महारत हासिल कर ली है और वहां सुगम कारोबारी माहौल है। इन्हीं सब कारणों से चीन दुनिया का कारखाना बन गया है।

अमित टंडन

अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में भी चीन जैसा बुनियादी ढांचा मिलने की उम्मीद शायद नहीं होगी। उन्हें यह भी नहीं लगता कि भारत में उनको चीन जैसे प्रशिक्षित श्रमबल की वजह से इतनी कुशलता के साथ कारोबार करने का मौका मिलेगा। इसलिए चीन प्लस वन असल में जोखिम कम करने की नीति है। दूसरे देश अगर चीन से हटने की नीति का फायदा उठाना चाहते हैं तो उन्हें हर तरह की तसल्ली देनी होगी।

भारत में कामकाजी आबादी की उम्र कम है और मध्य वर्ग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आने वाले दशकों में खपत बढ़ेगी। मगर हाल में काफी निवेश और सुधार के बाद भी भारत को अपना बुनियादी ढांचा बेहतर बनाने की जरूरत है। लोकतंत्र, पारदर्शिता और कानून का शासन आदि भारत की सकारात्मक बातें हैं मगर कारोबार को फलने-फूलने के लिए और भी काफी कुछ चाहिए। उत्पादक श्रम शक्ति को प्रशिक्षित श्रमबल की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और बेहतर जीवन सुविधाएं आदि जरूरी क्षेत्र हैं, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा मजबूत न्यायपालिका, स्वतंत्र संस्थान, स्थिर नीतियों और निरंतरता वाली कर प्रणाली आदि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारत में मजबूत अधोसंरचना तैयार करने और भूराजनीतिक रणनीति में गहराई लाने के लिए भारत सरकार ने निजी क्षेत्र की पूंजी का इस्तेमाल करने की ठानी। उसे पता है कि वह स्वयं एक सीमा तक ही खर्च कर सकती है। यही वजह है कि बड़े निजी समूह देश के रणनीतिक हित वाले क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जैसे रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर आदि। देश के कारोबारी जगत को वैश्विक पूंजी बाजारों से पूंजी जुटानी होगी। निस्संदेह ऐसा करने में वैश्विक स्तर पर उसकी छानबीन भी होगी।

इसीलिए दुनिया भर की सरकारें, कंपनियों के निदेशक मंडल और निवेशक अब इस बात पर नजर रखेंगे कि भारत इन घटनाओं पर क्या करता है। भारतीय नियामकों को मोटे तौर दुनिया के बेहतरीन नियामकों में शामिल किया जाता है और इस हकीकत को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देना चाहिए। भारत की रणनीतिक प्रगति में देर नहीं होने देनी है तो देश की नियामकीय व्यवस्था को तेजी से प्रतिक्रिया देनी होगी। विधि के शासन में भरोसा कायम रखकर तथा देश की व्यवस्थाओं पर यकीन करके ही 'मेक इन इंडिया' और 'विकसित भारत' का सपना साकार किया जा सकता है।

आपका पक्ष

कामकाजी महिलाओं का स्वास्थ्य: एक उपेक्षित मुद्दा

भारत में महिलाएं पारंपरिक रूप से परिवार की धुरी रही हैं। पिछले कुछ दशकों में कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के अनुसार, भारतीय कामकाजी महिलाएं घर और कार्यालय, दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। लेकिन, इस सबके बीच उनकी सेहत अक्सर उपेक्षित रह जाती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, प्रौद्योगिकी, डेटा, आपूर्ति और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं कंपनियों द्वारा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर उपेक्षित महसूस करती हैं। यह चिंताजनक है कि कंपनियां, जो महिलाओं को रोजगार देती हैं, उनकी सेहत के प्रति गंभीर नहीं हैं। हालांकि, कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम आयोजित करती हैं, लेकिन इनमें महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। महिलाओं की सेहत का मुद्दा न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी महत्त्वपूर्ण है। एक स्वस्थ महिला अधिक उत्पादक होती है और राष्ट्र के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है। एक अध्ययन के अनुसार, अगर कंपनियां महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो वे 22 प्रतिशत तक उत्पादन और 18 प्रतिशत तक अधिक मुनाफा कमा सकती हैं।

राजूराम प्रजापत, नागौर

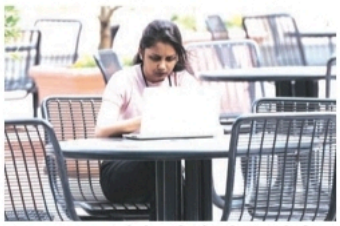

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मुताबिक देश की कामकाजी महिलाएं घर व कार्यालय में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं

एफटीए और निवेश: भारत के आर्थिक विकास का पथ

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया का मत भारतीय आर्थिक नीति और विकास के लिए एक सटीक मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने भारत की आर्थिक उन्नति और वैश्विक व्यापार में मजबूत स्थिति के लिए चीन से निवेश को सावधानीपूर्वक स्वीकारने की आवश्यकता पर बल दिया है। पानगड़िया ने अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों के उदाहरण देकर भारत को संवेदनशील क्षेत्रों से हटकर अन्य क्षेत्रों में चीन के निवेश का स्वागत करने की सलाह दी है। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। उसकी तकनीकी प्रगति और उत्पादन दक्षता भारत के औद्योगिक विकास को नया आयाम दे सकती है। चीन की कंपनियां उन्नत तकनीक और कौशल से भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बना सकती हैं, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता और निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, चीन की उपभोक्ता मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक उसकी पहुंच भारत के लिए नए आर्थिक अवसर उत्पन्न कर सकती है। हालांकि, चीन से निवेश के साथ सुरक्षा और क्षेत्रीय असमानता जैसी चुनौतियां भी जुड़ी हैं। पानगड़िया ने रक्षा, डेटा सुरक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के प्रति सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को आर्थिक प्रगति का महत्त्वपूर्ण उपकरण बताया। एफटीए के माध्यम से भारत अपने उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाकर उत्पादन लागत कम कर सकता है। पानगड़िया का दृष्टिकोण भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर सुदृढ़ करने के साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बल प्रदान करता है।

प्रो. आरके जैन, बड़वानी

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 23वीं बरसी पर शुक्रवार को सुरक्षा बलों के जवानों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

युवाओं की भूमिका

मोदी का दृष्टिकोण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया की चुनौतियों से निपटने में रचनात्मकता एवं तकनीक के साथ युवाओं की भूमिका पर जोर दिया है। एलेन की ने कहा है कि भविष्य के अनुमान का सर्वोत्तम तरीका उसे खोजना है और यह बात राष्ट्र के लिए भी सही है। खोजने तथा अपनी समस्याओं के समाधान तलाशने वाला देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ता है। इसी भावना को अभिव्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र-निर्माण में खोज की केन्द्रीय भूमिका पर जोर दिया है। 'स्मार्ट इंडिया हैकथान'-एसआईएच, 2024 में अपने संबाद के दौरान उन्होंने जोर दिया कि युवा मस्तिष्क खोजी ढंग से रचनात्मकता एवं तकनीक का प्रयोग कर भविष्य को स्वरूप दे रहे हैं। इस आयोजन में पूरे भारत की 1300 से अधिक टीमों ने भाग लिया और इसमें असली दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण विचार प्रदर्शित किए गए। एसआईएच आत्मनिर्भर भारत बनाने में शिक्षा और खोज की परिवर्तनकारी शक्ति प्रदर्शित का माध्यम है। इस आयोजन ने न केवल अकादमिक व उद्योग क्षेत्र के बीच खाई पाटने का प्रयास किया, बल्कि समस्या-समाधान के लिए सहयोगी संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। पहली बार साफ्टवेयर संस्करण के फाइनल का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी-एनआईटी श्रीनगर ने किया। यह 21 राज्यों की 25 उल्लेखनीय टीमों ने अपने खोजी समाधान प्रस्तुत किए।

इस हैकेथान में 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों-पीएसयू तथा उद्योगों द्वारा प्रस्तुत 250 समस्याओं के समाधान पेश

किए गए जिनमें स्वास्थ्यरक्षा, टिकाऊ विकास, शिक्षा, आपदा प्रबंधन व कृषि जैसे क्षेत्र शामिल थे। पिछले साल की तुलना में प्रतिभागियों में 240 प्रतिशत वृद्धि के साथ एसआईएच, 2024 अब तक का सबसे बड़ा आयोजन सिद्ध हुआ है। इसमें संस्थागत स्तर पर 86,000 से अधिक टीमों ने तथा राष्ट्रीय स्तर पर 49,000 टीमों ने भाग लिया। उल्लेखनीय प्रतिभागियों में एनआईटी श्रीनगर की 'विंग ब्रेन्स टीम' शामिल थी जिसका नेतृत्व साईदा आलेमिन डी. सलीम ने किया। इस टीम ने एआई-संचालित 'वर्चुअल रियलिटी प्रेंड' का विकास किया। यह पूल आटिज्म-प्रभावित विकृतियों तथा बौद्धिक दिव्यांगताओं से प्रभावित बच्चों की सहायता करेगा। सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के तत्वावधान में विकसित इस परियोजना का उद्देश्य उत्प्रेरित परिवेश में बच्चों के सामाजिक व संवादात्मक कौशल को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीम के दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए जोर दिया कि ऐसे समाधानों की वैश्विक प्रासांगिकता है और वे लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। सहभागियों से प्रधानमंत्री मोदी के संवाद में 'वैश्विक चुनौतियों के समाधान में स्थानीय खोज' का दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ। उन्होंने जोर दिया कि भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए खोजे समाधानों का वैश्विक महत्व हो सकता है और इससे दुनिया की प्रगति सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, 'हर बच्चे को प्रगति करने और समृद्ध बनने का अधिकार है। ऐसे खोजी समाधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई पीछे न छूटने पाए।' युवा मस्तिष्कों को खोजने, सहयोग करने तथा आविष्कार करने का मंच प्रदान करने वाला 'स्मार्ट इंडिया हैकथान' अगली पीढ़ी के नेताओं तथा समस्याओं के समाधानकर्ताओं को स्वरूप दे रहा है। वर्तमान समय में भारत स्वयं को वैश्विक खोज केन्द्र के रूप में विकसित कर रहा है। ऐसे में 'स्मार्ट इंडिया हैकथान'-एसआईएच जैसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। श्रीनगर, एनआईटी की इस आयोजन में महत्वपूर्ण सहभागिता से जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय छवि बदलने में भी योगदान मिलेगा। इस आयोजन से जहां शिक्षा और तकनीक की राष्ट्र-निर्माण में परिवर्तनकारी शक्ति प्रदर्शित होती है, वहीं यह भी स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद लोकतांत्रिक जम्मू कश्मीर पूरे देश के साथ कंधे से कंधा मिला कर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है।

सेवा भावना में एआई का योगदान

प्रयासों को सहज बनाने तथा समावेशन में वृद्धि से एआई स्वयंसेवकों को जोड़ने तथा उनका प्रभाव बढ़ाने में अपना योगदान कर रहा है।

राजदीप पाठक
(लेखक, गांधी दर्शन एवं स्मृति समिति से संबंधित हैं)

स्वयंसेवक लंबे समय से सामुदायिक विकास, सामाजिक परिवर्तन तथा वैश्विक एकजुटता का महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने समाज में महत्वपूर्ण व्यक्तिगत योगदान दिया है तथा व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ावा दिया है। वर्तमान परस्पर जुड़ी तथा तेजी से बदल रही दुनिया में स्वयंसेवा की अवधारणा में भी व्यापक परिवर्तन हो रहा है जिसमें तकनीकी प्रगति अपनी उल्लेखनीय भूमिका अदा कर रही है। विश्व स्तर पर 5 दिसंबर, 2024 को मनाए गए 'अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस'-आईवीडी की थीम 'आर्थिक एवं सामाजिक विकास' थी। इसने बेहतर दुनिया बनाने में स्वयंसेवकों की केन्द्रीय भूमिका पर जोर दिया।

इसके अंतर्गत विचार-विमर्श के विभिन्न क्षेत्रों में संकटों से निपटने में योगदान तथा प्राकृतिक विभीषिकाओं, मानव-निर्मित संकटों या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित गरीब व हाशियाकृत समुदाय के संकट दूर करने को शामिल किया गया। स्वयंसेवकों ने लगातार आपदा प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए उन क्षेत्रों में योगदान किया है जहां अक्सर सरकारें तथा संगठन अपनी सीमाओं से मुकाबला करते दिखते हैं। वैश्विक महामारी, प्राकृतिक विभीषिकाओं, मानवीय आपातकाल आदि स्थितियों में उनकी भूमिका अपरिहार्य रही है और खासकर वे संकटग्रस्त जनसंख्या की सहायता करने में सफल हुए हैं। उत्कृष्ट तकनीकों, खासकर 'आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस'-एआई इस स्वयंसेवा क्षेत्र को उल्लेखनीय रूप से नया स्वरूप प्रदान कर रही है। एआई से स्वयंसेवी पहलों की प्रभावशीलता, समावेशन व पहुंच में बढ़ावा मिलता है और इनका दूरगामी प्रभाव होता है। एआई-संचालित टूलों के प्रयोग से संगठन ऐसे प्लेटफार्म बना रहे हैं जो स्वयंसेवकों के कौशल को जोड़ कर उनके लिए अवसर बढ़ाते हैं, विसंगतियों को दूर करते हैं तथा प्रयासों को अधिकतम स्तर तक ले जाते हैं। इस परिवर्तन से न केवल स्वयंसेवकों का अनुभव समृद्ध होता है, बल्कि जरूरतमंद समुदायों को अधिकाधिक सकारात्मक लाभ भी मिलता है। एआई-संचालित प्लेटफार्म, जैसे 'हेल्पफाइंडर' संगठनों और स्वयंसेवकों के बीच तालमेल बिठाने में क्रांतिकारी भूमिका अदा कर रहे हैं। व्यक्तिगत कौशलों, दिलचस्पियों तथा स्थितियों के डेटा का विश्लेषण कर ये प्लेटफार्म यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वयंसेवक अपना अधिकतम सार्थक योगदान कैसे दे सकते हैं। इस सटीकता से विसंगतियां कम होती हैं, स्वयंसेवकों को बनाए रखने में सहायता मिलती है तथा उनके भीतर संतुष्टि की भावना मजबूत होती है। संकट के समय एआई-संचालित व्यवस्थायें तेजी से डेटा का विश्लेषण कर प्रभावित क्षेत्रों और उपलब्ध स्वयंसेवकों का पता लगा सकती हैं। इससे प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवकों की तेजी से तैनाती सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय एआई-संचालित प्लेटफार्म 'वनरेस्क्यू' ने प्रभावितों का पता लगाने, उनको मानसिक सहायता देने तथा वितरण में सहायता कर स्वयंसेवकों के प्रयासों में महत्वपूर्ण समन्वय किया था। इससे संकट को दूर करने में अमूल्य सहायता मिली थी।

> **एआई-संचालित प्लेटफार्म, जैसे 'हेल्पफाइंडर' संगठनों और स्वयंसेवकों के बीच तालमेल बिठाने में क्रांतिकारी भूमिका अदा कर रहे हैं। व्यक्तिगत कौशलों, दिलचस्पियों तथा स्थितियों के डेटा का विश्लेषण कर ये प्लेटफार्म यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वयंसेवक अपना अधिकतम सार्थक योगदान कैसे दे सकते हैं।**

कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पहलों को भी एआई से लाभ मिलता है। 'बेनिफिटो' जैसे टूल कर्मचारियों को एकसाथ जोड़ कर उनको प्रोत्साहित कर स्वयंसेवी गतिविधियों में शामिल करते हैं। इससे संगठनात्मक लक्ष्यों की भी प्राप्ति होती है। इन समाधानों से समन्वय सहज बनाना सुनिश्चित होता है, स्वयंसेविता का प्रभाव बढ़ता है तथा सहभागियों में टिकाऊ रूप से जोश बना रहता है। एआई-संचालित चैटबोट ने लगातार समर्थन, सवालों के जवाब देने तथा प्रशिक्षण में सहायता से स्वयंसेवकों के अनुभव में योगदान किया है। 1.45 बिलियन जनसंख्या वाले देश भारत में सेवा की भावना संस्कृति में गहराई तक व्याप्त है। परिवार के मूल्यों, धार्मिक शिक्षाओं और सामुदायिक परंपराओं में दूसरों की सहायता पर जोर दिया जाता है।

आज एआई इन प्रयासों में योगदान कर रहा है। चैटबोट का प्रयोग टीकाकरण अभियानों, मातृ स्वास्थ्य, महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा तथा अनेक अन्य विषयों पर स्वयंसेवकों के सवालों का जवाब देने में होता है। ब्रिटेन में एआई-संचालित व्यवस्थाओं ने फूड बैंक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में योगदान कर संकटग्रस्त लोगों को किराने का सामान पहुंचाने में सहायता की है। इससे स्पष्ट होता है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन करने में तकनीक स्वयंसेवकों का कैसे सशक्तीकरण करती है। 'बी माई आईज' जैसी उल्लेखनीय पहलों से स्वयंसेवकों को दृष्टि विकलांग लोगों को सहायता करने में मदद मिलती है। 'गुडसैम' जैसे प्लेटफार्म प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को फौरन आपातकालीन सेवाओं से जुड़ने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए 'गुडसैम' से सतर्क किए गए स्वयंसेवक सीपीआर देने में सहायता कर सकते हैं या आटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर-एएएड्स का प्रयोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के पहुंचने से पहले कर सकते हैं। 'वर्चअल स्वयंसेवा' ने उन पेशेवरों का और क्षमता विस्तार किया है जो सुदूर क्षेत्रों से सलाह दे सकते हैं। 'कैचपायर' व संरा. की आनलाइन वालंटियर सेवा ने निगरानी, कानूनी सलाह, भाषा अनुवाद तथा अनेक अन्य क्षेत्रों में सहायता कर भौगोलिक सीमायें तोड़ी हैं तथा स्वयंसेवकों को ज्यादा समावेशी बनाया है। डिजिटल टूल्स ने स्वयंसेवा के क्षेत्र में आने वाली परंपरागत बाधायें तोड़ी हैं जिनमें भौतिक दूरी, समय की कमी तथा पहुंच जैसे मुद्दे शामिल हैं।

दिव्यांग लोगों, देखभाल करने वालों या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले अब अपने घर से स्वयंसेवक की तरह काम कर सकते हैं। इस समावेशन से 2024 'आईवीडी थीम' का जन्म हुआ है जिसने विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग सुनिश्चित करते हुए आर्थिक व सामाजिक विकास के साझा लक्ष्यों को मजबूत किया है। सही तकनीक और संसाधनों के प्रयोग से स्वयंसेवक एकसाथ काम कर अनेक वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। समुद्री तूफान, भूकंप व बाढ़ जैसी प्राकृतिक विभीषिकाओं में ड्रोन व एआई टूल्स से लैस स्वयंसेवक प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग कर प्रभावी रूप से सामग्री पहुंचा सकते हैं। 'जेलो' जैसे एप आपातकाल के दौरान सहज संप्रेषण सुनिश्चित कर समन्वय के लिए स्मार्टफोन को वाकी-टाकी में बदल देते हैं।

गरीबी और भूख जैसी समस्याओं का मुकाबला करने में स्वयंसेवक फूड बैंक, सामुदायिक किचन, आदि तरीकों से सहायता कर संसाधन प्रदान कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्राउडफंडिंग द्वारा तैयार 'शेयर द मील' जैसे डिजिटल टूल व्यक्तियों को एक सरल टैप के माध्यम से भोजन दान करने में सक्षम बनाते हैं। इससे वैश्विक भूख का मुकाबला करने में सहायता मिलती है। शिक्षा एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां तकनीक के समर्थन से स्वयंसेवकों ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

आनलाइन प्लेटफार्मों ने शिक्षा तक पहुंच का लोकतांत्रीकरण किया है और इसे दुर्गम तथा असेवित समुदायों तक पहुंचाया है। 'कोड आर्ग' जैसी पहलों ने स्वयंसेवकों को कोडिंग कौशलों में सक्षम बनाया है जिससे वे छात्रों को उपयुक्त टूल्स से लैस कर सकते हैं। इससे तकनीक-संचालित भविष्य सुनिश्चित होता है। जेंडर केन्द्रित स्वयंसेवक कार्यक्रम कानूनी सहायता के माध्यम से असमानता दूर करने का प्रयास करते हैं, महिला अधिकारों पर कौंसिलिंग व एडवोकेसी करते हैं तथा स्वयंसेवा भावना की परिवर्तनकारी शक्ति का और बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

पश्चिम एशिया के लिए भारत का दृष्टिकोण

> **मनामा वार्ता ने भारत को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करने हेतु एक मंच प्रदान किया।**

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

जबकि सीरिया में बहुत बड़ा शासन परिवर्तन हो रहा था, जिससे पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक मिश्रण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना थी, भारत के विदेश मंत्री मनामा वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बदलती गतिशीलता पर व्याख्यान दे रहे थे। मनामा वार्ता नीति निर्माताओं और मंत्रियों को पश्चिम एशिया की रणनीतिक रक्षा, सुरक्षा और विदेशी चुनौतियों पर चर्चा और बहस करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

सीरिया में तेजी से बदलते कथानक की पृष्ठभूमि में हो रहे संवाद ने भारत को इस क्षेत्र में और इसके लिए अपनी सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं पर विचार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। सीरिया पर लगभग 50 वर्षों तक असद वंश का शासन रहा है। हालांकि, इस वंशवादी शासन ने तुर्की और जॉर्डन की सीमा पर स्थित देश को एक क्रूर पुलिस राज्य में बदल दिया। रूस और ईरान रणनीतिक कारणों से असद वंश का समर्थन करते रहे हैं। ईरान ने इजरायल के खिलाफ प्रतिरोध की अपनी धुरी बनाने के लिए शासन का समर्थन किया, जबकि रूस के पास सीरिया में वायु सेना और नौसेना के अड्डे हैं।

वैश्विक नेता सीरिया के हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं, जबकि इजराइल पड़ोस में अपना युद्ध जारी रखे हुए है। गाजा और यूक्रेन में इजराइली सैनिकों के हमले ने ईरान और रूस को विचलित कर दिया, जिसके कारण पिछले हफ्ते बशर अल असद को सत्ता से बाहर होना पड़ा। हालांकि, कई लोगों के लिए चिंता की बात यह है कि विद्रोही नेता अबू मोहम्मद अल-जवलानी का उदय हो रहा है, जो अल कायदा का पूर्व सदस्य है। वंशवादी शासन के बावजूद सीरिया ने

एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दृष्टिकोण बनाए रखा, जहाँ अल्पसंख्यकों और विविध समूहों को कोई भेदभाव महसूस नहीं हुआ। कई लोगों को डर है कि अल कायदा की साख वाले विद्रोही नेता राज्य को एक कट्टरपंथी इस्लामवादी राष्ट्र में बदल सकते हैं। इजराइल सहित पड़ोस के लगभग हर देश इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। दिल्ली शासन परिवर्तन के प्रति उदासीन रही है, भले ही असद वंश कश्मीर पर भारत की स्थिति और इस्लामाबाद के साथ उसके रुख का समर्थन करता रहा हो। क्षेत्र में कोई भी अमित्र शासन भारत की स्थिति को कमजोर करेगा और सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। इस पृष्ठभूमि में, पश्चिम एशिया और हिंद-प्रशांत के कई नेताओं के साथ मनामा वार्ता ने जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। क्षेत्र को प्रभावित करने वाले चल रहे संघर्षों का उल्लेख करते हुए एस जयशंकर ने कहा, और यह आज गाजा से लेबनान और अब सीरिया तक भी फैल जाएगा।

लेकिन साथ ही, हमें इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी हितों के बारे में यथार्थवादी होना होगा... दूसरा राजनीतिक-कूटनीतिक सहयोग जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, वह वास्तव में ऐसे समय में है जब दुनिया ध्रुवीकृत है, अगर पूरी तरह हिंसक नहीं है, तो आप तनाव को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, आप संघर्ष को और फैलने से कैसे रोक सकते हैं। हाल के दिनों में, हम सभी के लिए, इजराइल और ईरान के बीच संबंध या इसकी अनुपस्थिति विशेष रूप से चिंता का विषय रही है, इसलिए हमारे कुछ कूटनीतिक प्रयास उस विशेष पहलू पर केंद्रित रहे हैं। लाल सागर में भी स्थिति रही है।

हम अब्राहम समझौते के समर्थक रहे हैं और कुछ साल पहले हमने आई2यू2 नामक एक समूह शुरू किया था, जिसमें भारत, इजरायल, अमेरिका और यूएई शामिल हैं। यह अभी भी अपेक्षाकृत शुरुआती चरण में है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह एक ऐसा समूह होगा जो आगे बढ़ेगा। पिछले दशक में भारत ने व्यापार-उन्मुख विदेश नीति का दृष्टिकोण अपनाया है, जहां, यह जानता है कि आर्थिक साझेदारी से अधिक कुछ भी देशों को बांधता नहीं है।

श्री जयशंकर ने उल्लेख किया कि भारत के पास दस सदस्यीय खाड़ी सहयोग परिषद के साथ लगभग 170-180 बिलियन डॉलर हैं और भूमध्य सागर के देशों के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध हैं। जनवरी से एक नया अमेरिकी राष्ट्रपति भी आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क होगा। रिश्ते सबसे अधिक आर्थिक और आपसी हितों पर आधारित होने की संभावना है।

आप की बात

डगमगा रही नाव

इन दिनों लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद राहुल गांधी के पास है एवं वही इंडिया गठबंधन के मुख्य नेता भी है। मगर कहां जा रहा है कि इन दिनों अब उनका दोनों ही जगह का नेता पद डगमगा रहा है। एक समय था जब राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव के बीच में काफी गहरी दोस्ती बताई जाती थी मगर अब लगता है कि दोनों के बीच में एक बड़ी लंबी कहासुनी चलने के बाद आपस में एक दरार बन गई है। इसका सबसे बड़ा कारण कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा होने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर डाका डालना। एक समय विधानसभा और लोकसभा का चुनाव दोनों ने मिलजुल कर साझेदारी में लड़ा था मगर इसमें कांग्रेस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई थी एवं यहां समाजवादी पार्टी का हि अधिक नुकसान हुआ था। फिर आज के समय में कांग्रेस की हालत इतनी अधिक खराब हो चुकी है कि वह अपने दम पर भी चुनाव नहीं जीत पा रही है। अतः अखिलेश यादव को अब यह बात समझ में आने लगी है एवं वह स्वयं ही आज कांग्रेस एवं राहुल गांधी से दूरी बनाने लगे हैं एवं इन दिनों जब से ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद स्वीकार करने की बात कही है तब से अखिलेश यादव ने भी उनके समर्थन का मन बना लिया है। आज लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद एवं इंडिया गठबंधन के नेता का पद राहुल गांधी से अब छिन सकता है।

- एमएम राजावत, शाजापुर

ब्रायन जॉनसन का दावा

अमेरिकी बिजनेस टायकून ब्रायन जॉनसन का मानना है कि बढ़ती उम्र को रोका जा सकता है। उन्होंने रिवर्स एजिंग नामक एक तकनीक का विकास किया है, जिसका उद्देश्य उम्र को बढ़ाने के बजाय उसे कम करना है। ब्रायन जॉनसन का मानना है कि उम्र को बढ़ाने के लिए हमें अपने शरीर की कोशिकाओं को युवा बनाए रखना होगा। इसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार की दवा का विकास किया है, जो कोशिकाओं को युवा बनाए रखने में मदद करती है। रिवर्स एजिंग तकनीक के अलावा, ब्रायन जॉनसन ने एक विशेष प्रकार के आहार का भी विकास किया है, जो उम्र को बढ़ाने में मदद करता है। इस आहार में विशेष प्रकार के फल, सब्जियां और अनाज शामिल हैं, जो कोशिकाओं को युवा बनाए रखने में मदद करते हैं। ब्रायन जॉनसन की रिवर्स एजिंग तकनीक के बारे में वैज्ञानिक समुदाय में बहुत उत्साह है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक उम्र को बढ़ाने के लिए एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। हालांकि, रिवर्स एजिंग तकनीक के बारे में कुछ चिंताएं भी हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और इसके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। इसके अलावा, रिवर्स एजिंग तकनीक के बारे में नैतिक चिंताएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह तकनीक उम्र को बढ़ाने के लिए एक अनुचित तरीका है।

-सुभाष चुड़ावनवाला, रतलाम

पक्षपाती व्यवहार

इसमें कोई सन्देश नहीं है ना ही किसी की इस पर दो राय है की उपराष्ट्रपति एवं राजयसभा का सभापति श्री जगदीप धनकड़ का संबंध सत्तारूढ़ दल के साथ है। उसी पार्टी के बदौलत ही ये साहब इस मकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन इस पद को पाने के बाद जिसे, लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में सभी ने निष्पक्ष रखा है या रखने की कोशिश की है। मगर धनकड़ साहब पहले दिन से ही खुद को सत्ताधारी मान रहे हैं और विपक्षी राज्यसभा सांसदों को अपना दुशमन मान रहे हैं। यही वजह है की इतिहास में पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ, इस देश का विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विस्तार के साथ बताया की कैसे खुल्लमखुल्ला पक्षपात के मसीहा हैं जगदीप धनकड़ जी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में विपक्ष को लगातार टोकते हैं और अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं देते हैं। वह सत्ता पक्ष के सांसदों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री को कुछ भी कहने देते हैं,. जबकि विपक्ष पर अपनी बात को सुबूतों के आधार पर प्रमाणित करने को कहा जाता है और ऐसा नहीं करने पर कार्यवाही करने की धमकी दी जाती है। सभापति अपने अधिकारों का ग़लत इस्तेमाल कर रहे हैं ,और कई बार बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया है. साथ ही वो सदन के बाहर भी विपक्षी नेताओं की आलोचना कर चुके हैं।

- जंगबहादुर सिंह, जमशेदपुर

ठंड से बचाव

मालवा-निमाड़ अंचल में सुबह-शाम ठंड का असर खबर पड़ी। मप्र के कई पहाड़ी क्षेत्रों में पारा कांपी नीचे तथा कई जगहों पर ओस की बूंदें जमी। पाला पड़ने की संभावना हो सकती है जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। तेज ठंड का असर सामान्य जनजीवन पर हुआ है। मौसम में आए बदलाव और तापमान में भारी गिरावट के कारण चिंता बढ़ गई।कई लोग छोटे बच्चों को कड़ाके की ठंड में मोटरसाइकिल पर बैठा कर घुमाने ले जाते है।ऐसे में छोटे बच्चों को ठंड लग कर वे बीमार हो जाते है।छोटे बच्चों के शरीर की मालिश ,गर्म कपड़ों को पहनाए जाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। घरों मे बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े, अलाव आदि की और ध्यान देना चाहिए।घर मे पशु पक्षियों के लिए भी ठंड से बचाव के उपाए, व्यवस्था की जाना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी गरीब ,मानसिक रोग से पीड़ित लोगों, की सहायता गर्म, कपड़े, कम्बल, एवं ठंड से बचाव हेतु अलाव ,बेसहारा लोगों के लिए रहने हेतु उचित व्यवस्था की जाना चाहिए।

- संजय वर्मा, मनावर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते हैं।

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शनिवार, 14 दिसंबर 2024

सबका साथ ज़रूरी

एक देश, एक चुनाव : मिलकर क़दम बढ़ाएं

एक देश एक चुनाव पर अमल की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विपक्षी पार्टियां अभी भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इसे अमल में लाने पर अडिग है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस पर किस तरह की रस्साकशी होती है।

विचार बुरा नहीं | वैसे मूल रूप से पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का विचार बुरा नहीं है। चाहे अलग-अलग चुनावों पर होने वाले खर्च की बात हो या सरकार के कामकाज में इसकी वजह से होने वाली दिक्कतों की या देश के राजनीतिक माहौल में बनने वाले तनाव की- हर तरह से यह बात सुविधाजनक लगती है कि पांच साल में एक ही बार पूरे देश के चुनाव करा लिए जाएं ताकि बाकी समय सारी सरकारें विकास कार्यों पर फोकस कर सकें।

संसद में हो खुली चर्चा

लोकतांत्रिक चेतना | सुविधा के इस तर्क से आगे बढ़ने पर लोकतांत्रिक चेतना का सवाल आता है। किसी भी लोकतंत्र में चुनावों को सिर्फ सुविधा और खर्च के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। लोकतंत्र चुनाव में वोट देने की प्रक्रिया तक सीमित रहने वाली चीज नहीं है। असल बात समाज की लोकतांत्रिक चेतना है। उसका मजबूत बने रहना और समय-समय पर शक्तिपूर्ण तरीकों से व्यक्त होते रहना जरूरी है। देश के अलग-अलग हिस्सों में समय-समय पर चुनाव होते रहें तो इस चेतना को निरंतरता मिलती है जो इसकी मजबूती को बनाए रखने में सहायक होती है।

व्यावहारिक पहलू | इसके साथ ही व्यवहार का पहलू भी जुड़ा है। लोकतंत्र एक जीवंत भाव है और यह सिर्फ स्थिरता में नहीं बल्कि अस्थिरता में भी खिलता है। ध्यान रहे, शुरुआती डेढ़ दशक तक देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सामान्य उतार-चढ़ावों के क्रम में ये अलग-अलग होने लगे। अगर एक साथ चुनाव शुरू कराने के बाद फिर से अविश्वास प्रस्ताव या खंडित जनादेश के चलते यह क्रम बिगड़ता है तो उसे बनावटी ढंग से एक साथ बनाए रखना लोकतांत्रिक सहजता के लिहाज से कितना उचित होगा, इस पर भी विचार करना जरूरी है।

क्षेत्रीय आकांक्षा | एक साथ चुनाव पर फैसला करते हुए क्षेत्रीय दलों के तर्क को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। उनकी इस बात में दम है कि एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं के मन पर राष्ट्रीय मसले हावी हो सकते हैं। बहरहाल, यह बिल अभी संसद में पेश किया जाना है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां इसके सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार-विमर्श होगा और फिर सभी पक्षों के हितों व तर्कों को ध्यान में रखते हुए ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।

दो दूनी चार

स्वस्थ हेल्थ इंश्योरेंस

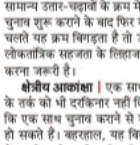

रमेश तिवारी

अमेरिका का नाम सुनते ही सुपर पावर की कल्पना की जाती है। कुछ साल पहले जब मैं वहां गया तो मैंने एक अलग ही रूप देखा। एक अमेरिकी नागरिक से मैंने पूछा कि यहां जिंदगी का सबसे कठिन पहलू क्या है। जवाब मिला- स्वास्थ्य सेवाएं। असल में इन सेवाओं की उपलब्धता बीमे पर टिकी है। इस तरीके से इलाज कितना आसान है, इस पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। हाल में इसकी आवाजें तेज हो गईं।

अमेरिका की एक बड़ी निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनी के सीईओ की हाल में हत्या हो गई। उनके हत्यारे से जो जानकारी सामने आई, उससे माना जा रहा है कि यह हमला इंडस्ट्री की कमियों के खिलाफ हुआ। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से और शिकायतों का सैलाब उमड़ पड़ा। कंपनी ने हत्या की जानकारी देने के लिए जो फेसबुक पोस्ट जारी की, उस पर प्रतिक्रिया में 57,000 हंसी वाले इमोजी मिले। लेकिन उद्योगपतियों की हत्या कॉरपोरेट गड़बड़ियों का जवाब नहीं हो सकती।

जिस कंपनी के सीईओ की हत्या हुई, वह अमेरिका की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मानी जाती है। रिपोर्ट आई है कि दावों के निपटान में यह कंपनी काफी पीछे थी। देरी दावे रिजेक्ट कर दिए जाते थे। कंपियों की बात भारत में भी लागू होती है। यहां कोविड के बाद से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का चलन तेजी से बढ़ा है। दो साल पहले इस बीमे का औसत क्लेम 62 हजार रुपये होता था, आज यह 81 हजार रुपये है। नतीजतन बीमा तेजी से महंगा हो रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि लोग बैंकों और एजेंटों के माध्यम से इसे खरीदना चाहते हैं, जिन्हें बीमा कंपनी कमिशन देती है। महंगे बीमे के बाद भी अक्सर शिकायत आती है कि बीमा कंपनियां क्लेम देने में देरी करती हैं, दावे को नामंजूर भी कर देती हैं। इसके पीछे रिटर्न को मैक्सिमम करने की नीति होती है। हाल में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत की 20 प्राइवेट बीमा कंपनियों का आकलन था। कहा गया था कि इनमें यदि किसी मरीज ने अस्पताल बिल के रूप में एक लाख रुपये का दावा किया, तो बीमा कंपनी ने 80,000 रुपये से कम का भुगतान किया।

सरकार की ओर से भी स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादातर मुफ्त मिलती हैं, लेकिन भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में यह मॉडल जनता को ज्यादा पसंद नहीं आता। दुनिया में पहली बार ब्रिटेन में फीस या बीमा के भुगतान के बजाय पूरी तरह से मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई थी। उसे भी आज नाकाम देखा जा रहा है।

हमारा देश बीमा संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत ने इसे आगे बढ़ाने में मदद की है, जो फिलहाल मुफ्त है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को शक रहता है कि उनका अनावश्यक इलाज न हो जाए। हाल में गुजरात में आयुष्मान भारत योजना के दो लाभार्थियों की एक निजी अस्पताल में एंजियोप्लास्टी के बाद मौत हो गई। आरोप लगे हैं कि उन्हें इस सर्जरी की जरूरत ही नहीं थी।

बीमे की गड़बड़ियों से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं, यह जानने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत है। इस इंडस्ट्री के लोग ही प्रस्ताव रख चुके हैं कि अस्पताल ही बीमा सेवा मुहैया कराएं। इससे बीमा के नाम पर लूट कम हो सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर को और अधिकार दिए जाने की वकालत की जा रही है।

ऑफ़ दि ट्रैक

रील्स का प्रदूषण

राहुल पाण्डेय

इन दिनों हर कोई रील्स या शॉर्ट विडियो खूब बनाता है, और रील्स खूब देखी भी जाती हैं। इन्हें देखते-देखते वक्त कैसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन ये रील्स कुछ और भी बना रही हैं, कुछ ऐसा- जिसकी वजह से इन दिनों पूरी धरती ही डांवाडोल है। पेरिस स्थित कार्बन अकाउंटिंग कंसल्टेंसी Greenly का कहना है कि TikTok हर साल जितना कार्बन पैदा कर रहा है, वह ग्रीस जैसे देश से भी ज्यादा हो सकता है। एक औसत टिकटॉकिया हर साल जितनी ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है, उससे 198 किग्रा कार्बन चल सकती है। 2023 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में TikTok ने लगभग 7.6 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर प्रदूषण पैदा किया है। यह भी सिर्फ कुल उत्सर्जन का 15% हिस्सा है। अंदाजा है कि 50 मिलियन मीट्रिक टन सिर्फ इसके डेटा सेंटर से निकला कार्बन है। इसमें TikTok के दफ्तरों का भी जोड़ दें तो यह ग्रीस को भी पार कर जाएगा। 2023 में ग्रीस का कार्बन उत्सर्जन 51.67 मिलियन मीट्रिक टन था। शोधकर्ताओं ने पाया कि TikTok यूजर से प्रति वर्ष औसतन 48.49 किग्रा CO2e, YouTube यूजर 40.17 किग्रा और Instagram यूजर 32.52 किग्रा CO2e आता है। यानी अब से रील बनाएं या देखें तो एक बार यह जरूर सोच लें कि रील भी धुआं छोड़ती है, बस वह गाड़ियों, मिलों या पराली की तरह सामने नहीं दिखता।

दिल्ली एम्स में दम तोड़ने से पहले दिग्गज अभिनेता ने क्या कहा था

राज साहब के आख़िरी शब्द!

प्रदीप सरदाना

सौ बरस पहले 14 दिसंबर 1924 को जब पेशावर में राज कपूर का जन्म हुआ, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह बालक विश्वभर में इतना मशहूर हो जाएगा। हालांकि तब सिनेमा में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था लेकिन नीली आंखों वाले राज कपूर ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से, समस्त नीले आकाश को ऐसा जगमग किया कि फिल्मी कलाकार सितारे कहलाने लगे। आने वाली पीढ़ियां ही नहीं, पिछली पीढ़ियां भी उसी राज कपूर के नाम से रोशन हो गईं।

इसकी हालिया मिसाल कपूर परिवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चित मुलाकात भी है। यह पहला मौका था जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने फिल्म संसार के किसी एक परिवार के सारे सदस्यों के साथ इतनी आत्मीयता एवं सम्मान से भेंट की। मोदी ने राज कपूर की 'सॉफ्ट पावर', उनकी फिल्मों और उनके योगदान का जिक्र किया तो कपूर परिवार अभिभूत हो गया।

फिल्मों में कपूर परिवार की नींव 1927 में यूं तो पृथ्वीराज कपूर ने रखी। लेकिन बड़े बेटे राज ने फिल्म उद्योग के सबसे बड़े परिवार के रूप में ख्याति दिलाई। राज कपूर स्वयं तो फिल्मों में आए ही, अपने भाई शम्मी-शशि, बेटे रणधीर, ऋषि और उनके भी इंडस्ट्री में लेकर आए। यहां तक कि अपने दादा बशेश्वरनाथ कपूर और पिता पृथ्वीराज को भी अपनी 'आवारा' फिल्म में साथ काम करवाया। राज कपूर ने करीब 60 फिल्मों में अभिनय किया। अपने आरके बैनर से 18 फिल्मों का निर्माण किया।

अपने अभिनय जीवन की शुरुआत राज ने पिता से प्रेरित होकर ही की थी। वही राज कपूर के गुरु थे। हालांकि पिता और पुत्र की उम्र में मात्र 18 बरस का फासला था। राज ने 5 बरस की उम्र में एक नाटक 'द टॉप कार्ट' में अभिनय किया तो उसके लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। बस तभी से उन्हें लगा कि अभिनय ही उनका जीवन है। इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान न देकर वह रंगमंच और फिल्मों में काम करने के लिए मचल उठे।

यूं थोड़ा बड़ा होने पर राज ने स्कूल के एक नाटक में काम किया तो वह कुछ ऐसा कर गए कि निर्देशक ने उन्हें गले से पकड़ कर कहा तुम गधे हो, यहां फिर कभी न आना। इसके कुछ बरस बाद सीखने के लिए राज, फिल्मकार केदार शर्मा के सहायक बने तो वहां शॉट से पहले क्लैप को इतने जोर से दबाया कि अभिनेता की दाढ़ी ही उसमें फंस गई। इस पर केदार ने उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सन 1948 में जब राज ने अपनी पहली फिल्म 'आग' बनाई तो वह बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 1949 में 'बरसात' से उन्हें जो सफलता मिली, उसी से संकेत मिल गए कि भारतीय सिनेमा को एक मसीहा मिल गया है। 1951 में 'आवारा' ने उन्हें ग्रेट शोमैन का खिताब दिलवाया। 'आवारा' के कारण ही राज देश की ऐसी पहली फिल्म हस्ती बने, जिनकी लोकप्रियता विदेशों में पहुंची। रूस में भी वह आज तक महानायक माने जाते हैं।

राज कपूर की फिल्मों की खूबियां देखें तो उनमें कथानक, अभिनय के साथ संगीत भी बेहद खूबसूरत रहा। अपने बचपन में सफेद साड़ी पहने एक महिला की छवि उनके अन्तर्मन में ऐसे बसी कि अपनी सभी नायिकाओं को उन्होंने सफेद साड़ी जरूर पहनाई।

राज कपूर ने जहां श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली जैसी भव्य फिल्में बनाईं। वहीं, विभिन्न समस्याओं पर बूट पालिश, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है और अब दिल्ली दूर नहीं जैसी कलात्मक फिल्में भी दीं।

राज कपूर की फिल्में जहां व्यावसायिक दृष्टि से बहुत सफल रहीं वहीं फिल्मफेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी इनकी झोली भरती रही। भारतीय सिनेमा के शिखर पुरस्कार 'दादा साहब फाल्के' को लेने राज कपूर जब 2 मई 1988 को दिल्ली आए, तो समारोह के दौरान ही उन्हें अस्थमा का भयावह दौरा पड़ा। इसे संयोग कहें कि उनके भरे-पूरे परिवार के होते हुए भी उस अंतिम समय में, उनकी पत्नी कृष्णा कपूर के साथ मैं ही था। मैं ही उन्हें राष्ट्रपति भवन की एंबुलेंस में सिरी फोर्ट से एम्स ले गया। जहां मैं लगातार उनके साथ रहा। रात को उनकी तबीयत बिगड़ी तो आईसीयू में उनके पलंग के एक ओर मैं तो दूसरी ओर कृष्णा जी थीं। राज कपूर मेरे साथ अपने व्यक्तिगत जीवन का अंतिम संवाद करते हुए कोमा में चले गए। मेरे साथ उनके अंतिम शब्द थे- 'मुझे आराम नहीं आ रहा है। मैं अब ठीक नहीं हो सकूंगा, लेट भी डार्ड।' इसके बाद वह सदा के लिए मौन हो गए। एक माह तक अचेतावस्था में रहने के बाद उनका निधन 2 जून को हुआ। आज राज कपूर चाहे शरीर के साथ हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन अपनी फिल्मों और संस्मरणों से वह सदियों तक हमारे बीच रहेंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक हैं)

शताब्दी का फिल्मकार

- कपूर परिवार को राज की वजह से मिली ख्याति
- आरके बैनर के तहत 18 फिल्मों का निर्माण
- रूस में आज भी राज को लोग मानते हैं महानायक

ग्रोथ या छलावा

शेख हसीना के दौर में पूरी दुनिया बांग्लादेश की ग्रोथ को सराह रही थी। एक वक्त तो उसकी रफ्तार ने एशिया में भारत को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन, एक रिपोर्ट कहती है कि यह सब धोखा था।

सरकारी भ्रम

अंतरिम सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के सही आकलन के लिए एक एक्सपर्ट टीम बनाई। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में देश की ग्रोथ केवल 3% रही, न कि 7% । आरोप है कि डेटा के साथ खिलवाड़ किया गया था।

सबसे बड़ा करप्शन

रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा यह है कि 2009 से 2023 के दौरान करीब 234 बिलियन डॉलर बांग्लादेश के बाहर भेजे गए। यानी हर साल GDP का 3.4% हिस्सा बाहर भेजा गया।

ग्रोथ में गिरावट

वर्ल्ड बैंक और एशियन डिवेलपमेंट बैंक, दोनों का अनुमान है कि 2023 के मुकाबले मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास दर में कमी आएगी। 2024 में GDP ग्रोथ 5.2% हो सकती है। अगले साल इसके 5.1% होने का अनुमान है। मौजूदा साल में महंगाई दर 9.7% रही और 2025 में भी इससे शायद ही राहत मिले। यह 10% को पार कर सकती है।

गरीबी की गिरफ्त

विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश में गरीबी दर 2010 के 49.6% के आंकड़े से 2022 में 30% पर आ गई। लेकिन, इस आबादी के फिर से गरीबी में फंसने की आशंका बढ़ गई है। इससे बचने के लिए नए सिरे से आर्थिक सुधार करने होंगे।

राजनीतिक अस्थिरता

बांग्लादेश की तरक्की का बुलबुला अचानक फूटा है। तो इसके पीछे राजनीतिक अस्थिरता भी वजह है। निजी निवेश घटा है। अंतरिम सरकार निवेशकों को देश में पैसा लगाने के लिए भरोसे में नहीं ले पा रही।

प्रस्तुति : शैलेंद्र पांडेय

www.nbt.in

दोनों ने की एक-सी भूल

खुद अपनी आंख से

सरस्वती रमेश

मौसी मेरे घर के पास रहती थीं। उनकी बेटी दीप्ति भी हमउम्र थी, इसलिए मैं उनके घर खूब आती-जाती। हालांकि हमारे स्कूल अलग थे। एक दिन की बात है। दीप्ति के स्कूल की सहेली का जन्मदिन था। वह जाने की जिद करने लगी। मगर मौसा ने सख्ती से मना कर दिया। उसकी सहेली का घर बाजार के उत्तर में था और हमारा दक्षिण में। मौसी के दांत में कई दिनों से दर्द था, और उसी दिन उन्हें दांत निकलवाने डॉक्टर के पास जाना था। दीप्ति अपनी मम्मी से झिंमियाते हुए बोली, 'मम्मी प्लीज मुझे भी ले चलो। तुम बाजार में डॉक्टर के पास चली जाना और मैं इतनी देर में जन्मदिन मनाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी।' सहेली का घर कॉटन मिल के आगे पड़ता था। बाजार उससे पहले था। उसकी मम्मी मान गईं। बाजार पहुंच कर दीप्ति ने सहेली के लिए एक चमचमाता गिफ्ट खरीदा और जाने लगी। 'एक घंटे में लौट आना। मैं यहीं हूं।' मौसी ने कहा।

सहेली के पास पहुंचकर दीप्ति धुल गई कि उसकी मम्मी ने उसे घंटे भर में वापस बुलाया है। जब दो-ढाई घंटे बीत गए तो मौसी पागलों की तरह उसे कॉटन मिल के आसपास खोजने लगी। मैं स्कूल से वापस आ रही थी। मौसी रास्ते में दिख गईं। मुझे देखते ही बदहवास हो बोलीं, 'तुम पूजा का घर जानती हो क्या?' मैंने कहा 'नहीं।' हम साथ में पूजा का घर खोजने लगे। हमें उसके मम्मी-पापा का नाम नहीं पता था। मौसी की बेचैनी देख मुझे रोना आ रहा था और दीप्ति की नादानी पर गुस्सा। कॉटन मिल कई वर्षों से बंद पड़ी थी। मुख्य गेट के पास थोड़ी सी दीवार टूटी थी। वह रास्ता भी कुछ सूना था। दोपहर में इक्का-दुक्का लोग या स्कूली बच्चे ही दिखते। मौसी की आशंका हुई। लौटते वक्त कहीं दीप्ति को पकड़कर कोई मिल में न ले गया हो! हम दीवार के उस छोटे से छेद से मिल में घुस गए। भीतर जंगल झाड़ियां, बड़े-बड़े टिन शेड और सांय-सांय करता सन्नाटा था। दिन में भी रात जितना डरावना। ज्यादा अंदर जाने की हमारी हिम्मत न हुई। सामने-सामने खोजकर हम लौट आए।

दोपहर से शाम होने को आई। उखड़े दांत की पीड़ा भूल मौसी सड़क के किनारे उदास बैठ गईं। तभी सामने दीप्ति आती दिखी। मौसी दौड़ते हुए उसके पास गईं और उससे लिपट कर रोने लगीं। दीप्ति पर बिना बिफरे, बिना कुछ कहे । बस उससे लिपट कर रोती रही। ऐसे, जैसे दीप्ति वर्षों से लापता हो और आज मिली। दीप्ति को अहसास हो गया कि उसने बहुत देर कर दी। इतनी कि मम्मी रो पड़े। वह मौसी के आंसू पोंछते हुए बोली, 'मुझे माफ कर दो मम्मी। अब मैं कभी सहेली के जन्मदिन में नहीं जाऊंगी।' मौसी ने आंसुओं से डूबे हुए ही सिर हिला दिया।

हम घर की ओर चल पड़े। मगर आज मां बाहर ही मिल गईं। मुझे देखते ही लपककर बाहों में भर लिया। बोलीं, 'तुम्हारे स्कूल की लड़कियां कब की आ चुकीं। तुम कहां थी मेरी बच्ची? मैं कब से छटपटा रही हूं।' मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी मां भी मेरी राह देख रही होंगी। मैं पछतावे से भर उठी। मैंने मां को सारी बात बता दी। उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मगर मुझे और दीप्ति को अपनी एक जैसी भूल का हमेशा मलाल रहा।

चलते-चलते...

कहते हैं, जैसा अन्न, वैसे हम। अब इसमें एक और चीज जुड़ गई है- वैसी ही भविष्य की पीढ़ियां। टुलेन यूनिवर्सिटी का शोध कहता है कि आहार में कमी का असर आपकी आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। एक पीढ़ी में अकाल पड़ने से अगली पीढ़ी में हानिकारक आनुवंशिक परिणाम हो सकते हैं। और ऐसा सिर्फ एक-दो पीढ़ी तक नहीं, बल्कि चार पीढ़ियों तक होता है।

संस्कृति में आ रहे बदलाव वापस नहीं होंगे

मशहूर लेखक अमिताव कुमार की पिछले दिनों हार्पर कॉलिंस से नई किताब आई है, जिसका नाम है **The Green Book**। *इससे पहले वह* **The Yellow Book** *और* **The Blue Book** *लिख चुके हैं। The Green Book में उन्होंने दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से लेकर भारत में हो रहे तेज सांस्कृतिक बदलावों का विस्तार से जिक्र तो किया ही है, साथ ही अपनी बनाई कई पेंटिंगों को भी शामिल किया है। न्यू यॉर्क के वासर कॉलेज में इंग्लिश के प्रफेसर अमिताव कुमार से इस किताब की विषयवस्तु पर बात की राहुल पाण्डेय ने। पेश है बातचीत के अहम अंश :*

साप्ताह का इंटरव्यू

अमिताव कुमार

■ आपने किताब की शुरुआत वृक्षों, खर-पतवार और पत्तों से की है। सभ्यता और जीवन में इन्हें कैसे देखें और एक गिरते हुए पत्ते को कैसे देखें?

पत्रकार और लेखक जेनेट मैल्कम की बनाई एक पत्ते की पेंटिंग है। यह कोई खास नहीं, खर-पतवार में पड़ा जाने वाला पत्ता है। अपनी किताब में वह पत्ते की तस्वीर को लेकर कहना चाहती थीं कि जिसे पालतू और बेकार समझा जाता है, ध्यान से देखें तो उसमें आप वैल्यू पाते हैं। लेकिन हम ध्यान से नहीं देखते। पेड़ों के साथ भी हम यही कर रहे हैं। मैं पेड़ों से डिसकशन इसलिए शुरू करना चाहता था ताकि ग्लोबल वॉर्मिंग का जो संकट है, वह आप पास से दिखे। साथ ही, पेड़ों की खूबसूरती को मैं थोड़ा पेंट भी करना चाहता था।

■ लेकिन यह नहीं बताया आपने, एक गिरते हुए पत्ते को कैसे देखें? आप कैसे देखते हैं?

आपने जटिल दार्शनिक प्रश्न किया है। दुष्यंत कुमार फरमाते हैं, 'जिएं तो अपने घर में गुलमोहर के तले। मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए।' यह जिंदगी के लिए एक मंत्र है। गिरते हुए पत्ते के बारे में एक डिस्कशन है। मैं टोरंटो से न्यू यॉर्क आ रहा था। नए स्कूल का पहला दिन था। मैं विलियम डेलरिंपल का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, लॉरेंस ऑफ अरेबिया पर। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने मरने के पहले लिखा था, 'क्या तुमने कभी खुद को एक पत्ता महसूस किया है, जो अपने पेड़ से पतझड़ में गिरा हो और इस बात को लेकर उत्साहन में पड़ा हो?' यह मुझे जरा छू गया, क्योंकि यह वही साल था जब मैंने पिता को खोया था। अब 60 की उम्र गुजरने के बाद लग रहा है कि जैसे अमरता छू गई हो। यह गिरते हुए पत्ते वाली बात अमरता और मृत्यु के बारे में है, और वह मुड़ते है इस किताब में भी, क्योंकि कुछ पनपता है, कुछ जन्म लेता है। प्रकृति में जन्म-मृत्यु की चक्र है। मैंने ऋषिकेश में देखा कि गंगा में लोग मस्ती में थे हैं, पूजा में भी जा रहे हैं और उधर बस कुछ दूर एक चिता पर किसी को जलाया जा रहा है। एक जापानी हाइकू कवि थे। उनका हाइकू है, 'यह ओस की दुनिया सिर्फ ओस की दुनिया है लेकिन फिर भी है, फिर भी है।' उस कवि के भी बच्चे मर गए थे। उसकी जिंदगी में त्रासदियां आती रहीं, फिर भी वह इस तरह की लाइनें लिखता रहा। मुझे लगा कि यही है। मृत्यु में भी कुछ और देखना, देख पाना और सोच पाना। 'ग्रीन बुक' तो यही हो गई।

■ आपने लेखक की नोटबुकों का जिक्र किया है। नोट्स से बुक बनने की प्रक्रिया के बारे में बताइए।

हमारी दुनिया में और खासकर पूंजीवाद में प्रॉडक्ट को खास महत्व दिया जाता है। फिनिश प्रॉडक्ट है, शेल्फ पर चमकता है, जिसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन हम लोगों को प्रॉडक्ट नहीं, प्रॉसेस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे कुछ बना। किसका श्रम उसमें था? किसे कितना वेतन मिला? वह कैसे लिखा गया, कहां से आया और उसके कल्पना के स्रोत क्या-क्या थे? उसमें मुझे नोटबुक का बहुत महत्व लगता है ताकि एक ओर से हम समझें कि किसी और लेखक ने किताब कैसे लिखी, उसकी सोच क्या थी, क्या-क्या उसके साथ हुआ? दूसरी ओर, एक डेमोक्रेटिक शेयरिंग हो सभी के साथ कि हमने ऐसे किताब लिखी। वीएस नायपॉल के छोटे भाई शिव नायपॉल शायद जरूरत पड़ कहीं थे, उन्होंने लिखा कि डायरी ना लिखो तो डिप्रेशन ब्लर पड़ जाते हैं। मैं भी इससे सहमत हूं कि अगर आप रोज नोट नहीं करें कि क्या हो रहा है तो सारे दिन एक-दूसरे से घ्लर करने लगते हैं और फिर लगता है कि सब कुछ बीत गया। और बीत ही नहीं गया, वह एक लॉस की तरह महसूस होता है। पहले मैं नोट्स नहीं बनाता था, और मुझे लगता है कि मैंने वे सारे साल गंवा दिए।

> हम सबकी जिंदगी मिली-जुली है। सारी धाराएं मिश्रित हैं। गंगा में कितनी सारी धाराएं मिलती हैं, तब जाकर गंगा बनती है। हरी भागीरथी तो मटमैली अलकनंदा, फिर सांवली यमुना। लेकिन रोज अखबार में पढ़ रहे हैं कि फलां ढांचे के नीचे तो कोई और इमारत थी। अरे भाई, हम लोगों का तो सारा इतिहास ही मिला-जुला है

■ आपने अपनी गंगा यात्रा के बारे में तफसील से लिखा है। कैसी रही यह यात्रा?

मेरे बाबू जी बोले थे कि मणिकर्णिका में ही हमारा अंतिम संस्कार करना। मणिकर्णिका तो ले गए उनको, लेकिन हमको भी लगा कि उनका यहां पर ही क्यों मन था? इस नदी की क्या अहमियत है? हमारी जो जिंदगी है, सब मिली-जुली सी है। सारी धाराएं मिश्रित हैं। गंगा में कितनी सारी धाराएं मिलती हैं, तब जाकर गंगा बनती है। हरी भागीरथी तो मटमैली अलकनंदा, फिर सांवली यमुना। लेकिन रोज अखबार में पढ़ रहे हैं कि फला ढांचे के नीचे तो कोई और इमारत थी। अरे भाई, हम लोगों का तो सारा इतिहास ही मिला-जुला है। आप और नीचे देखेंगे तो कुछ और भी दिख जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि गंगा का सिर्फ एक ही रंग हो।

■ आपने बढ़ती गर्मी का भी जिक्र किया है...

गर्मी में मैं भारत आया तो पत्रकार रवीश कुमार से पूछा कि एक्सेप्ती लोगों में बर्फ (snow) के लिए अगर 50 शब्द हैं, तो गर्मी के लिए आपने यहां क्यों इतने शब्द नहीं हैं? उन्होंने इस बात को ऐसे घुमाया, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वह बोले कि गर्मी के जितने शब्द हैं, अगर आप धूप जाएंगे तो आप यह भी धूप जाएंगे कि आपके बगल में कौन रहता था, किसने गर्मी आपके साथ सही थी। उनके भी नाम धूप जाएंगे। इसी भावना को मैंने ओइगी में कर दिया कि **heat**, many words for **hate**, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लाइमेट में जो बदलाव आ रहा है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकेगा। वे सारे ग्लेशियर वापस नहीं आएंगे। उसी तरह हमारे कल्चर में जो चेंज आ रहे हैं, जिस तरह से हम अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ भी कह दे रहे हैं या उनके घर हम बुलडोजर करते रहे हैं। या उनके साथ, उनकी औरतों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, यह हमारे नेता ऐलान कर देते हैं। इस तरह से कल्चर पर जो हो रहा है, उसको हम फिर रिपेयर नहीं कर पाएंगे। बुलडोजर ने संस्कृति का कितना नुकसान किया, कुछ अंदाजा लगा पाते हैं आप?

रीडर्स मेल

▸ वाकई बेमिसाल

भारतीय खिलाड़ी गुकेश ने जिस तरह से शतरंज में शह और मात देकर विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है, वह समूचे देश को लंबे समय तक गर्व करने का अवसर देता रहेगा। इस पर प्रकाशित संपादकीय 'बेमिसाल गुकेश' (13 दिसंबर) पढ़ने को मिला। 18 वर्ष की उम्र में डी. गुकेश का विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतना न केवल भारतीय शतरंज के लिए बल्कि समूचे खेल जगत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनकी मेहनत, लगन और धैर्य की जितनी सराहना की जाए, कम है। गुकेश की खेल शैली, उनकी सूझबूझ और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। विशेष रूप से, यह तथ्य कि उन्होंने दबावपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी गलतियों से सीखकर मुकाबले को अपने पक्ष में किया। यह सही है कि भारत में शतरंज जैसे खेलों को वह प्रोत्साहन और मान्यता नहीं मिलती, जो क्रिकेट को मिलती है। अब उम्मीद है कि अन्य खेलों को उतनी ही प्राथमिकता दी जाएगी और युवाओं को इन खेलों के लिए प्रेरित किया जाएगा।

प्रतिमा तिवारी, मयूर विहार

▸ नए सिरे से बहस हो

13 दिसंबर को संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख 'कौन है स्त्री-पुरुष का साझा दुश्मन' पढ़ा। लेख में पितृसत्ता के सब पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को जिस गहराई से समझाया गया है, वह सराहनीय है। पितृसत्ता न केवल महिलाओं पर अत्याचारों के लिए जिम्मेदार है, बल्कि बेगलुरु में इंजीनियर की सुसाइड बताती है कि यह पुरुषों के लिए भी बेहद हानिकारक है। लेकिन यह बात भी सही है कि पितृसत्ता से ग्रस्त पुरुष जब भी खुद के अंदर झांकते हैं, तो उनका व्यवहार महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतर होता जाता है। पितृसत्ता के कारण समाज में व्याप्त असमानता को गंभीरता से लेना होगा। समाज में नए सिरे से बहस शुरू करने की जरूरत है। खासतौर से इस बात पर कि पितृसत्ता का असर न केवल महिलाओं की आजादी पर, बल्कि पुरुषों की भावनात्मक अभिव्यक्ति पर भी पड़ता है।

सुमंत श्रीवास्तव, चुरहट

नवभारत टाइम्स, ई. 353,354 सांगानेर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302 029 से मुद्रित व प्रकाशित, मुख्यालय: एनबीटी बिल्डिंग, नवभारत टाइम्स मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **राष्ट्रीय प्रिंटिंग हाउस, बाइपास, औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद** और नोएडा प्लांट 2-ए, सेक्टर 80-81, इंडस्ट्रियल एरिया, नोएडा, उत्तरप्रदेश-201305 से मुद्रित। फोन : 0120-2420001 विज्ञापन कार्यालय : एनबीटी बिल्डिंग, नई दिल्ली-110002 विज्ञापन शुल्क : 5 वर्ग सेमी. न्यूनतम ₹ 600 मात्र। प्रोडक्शन के प्रतिनिधि : नियुक्ति ने ... प्रोडक्शन : नियुक्ति ने ... संपादक (रिजनल संस्करण) : राजीव पांडे (इस अंक में प्रकाशित समाचार कलकत्ता के साथ एवं संपादन हेतु पी.टी.आई. की एक्ज